वर्ष - 01, अंक - 01, दिसम्बर, 2022

द डाटा स्ट्रीट

THE DATA STREET

हिन्दी मासिक पत्रिका

महात्मा की अन्तरात्मा रो पड़ी

जब सुभाष के सैनिक लुटेरों के सरदार बने

दोस्तों,

पिछले ढाई दशक से हम डाटा से जुड़े कार्य कर रहे हैं। यूरीड मीडिया पोर्टल भी है। जिसमें निरंतर डाटा से जुड़ी खबरें एवं जानकारी आती रहती हैं। विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव परिणाम की विश्लेषणात्मक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। मेरे मित्र डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी की इच्छा थी कि डाटा नाम से कोई मासिक पत्रिका एवं पोर्टल शुरू किया जाए। जिसमें समाज से जुड़ी विभिन्न खबरें, चुनाव विश्लेषण व केंद्र एवं प्रदेश सरकार के योजनाओं की जमीनी हकीकत, डाटा आधारित जानकारी दी जाए। डॉक्टर चतुर्वेदी और मेरा 42 वर्षों से छात्र जीवन से सम्बन्ध रहा है। उनके इस प्रेरणा एवं सुझाव पर ही ''द डाटा स्ट्रीट'' पत्रिका और वेबसाइट/पोर्टल शुरू किया जा रहा है लेकिन मेरे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा है कि मेरे मित्र जिनके सुझावों एवं सहयोग से द डाटा स्ट्रीट मासिक पत्रिका व पोर्टल आरंम्भ करने जा रहा हूँ वह मेरे प्रिय अभिन्न मित्र डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी का एक गंभीर बीमारी के कारण 7 अक्टूबर 2022 को अचानक निधन हो गया। जिससे मुझे गहरा सदमा लगा लेकिन मैंने निश्चय किया कि डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी के सुझावों के अनुसार उनकी स्मृति में पत्रिका/पोर्टल की शुरूआत करूंगा। यह पहला अंक स्वर्गीय डॉ अनिल चतुर्वेदी को समर्पित है। जिसमें उनके लेख दिए जा रहे हैं।

पत्रिका एवं पोर्टल दोनों डाटा आधारित होंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास कि आपका सहयोग एवं आशीर्वाद पूर्व की भांति मिलता रहेगा।

सम्पादक
राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी

द डाटा स्ट्रीट
हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष - 01, अंक - 01, दिसम्बर, 2022

संरक्षक –
जस्टिस आर एन पाण्डेय
(पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद)

सम्पादक - राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी
स्थानीय संपादक - विजय शंकर पंकज
समाचार संपादक - सुजीत श्रीवास्तव
स्टेट ब्यूरो यू पी - अमन सिन्हा
ब्योरा चीफ - रोहित सिंह
यूपी-उत्तराखडं प्रभारी - जीतेन्द्र सिंह चौहान
दिल्ली ब्यूरो - अतुल कुमार
कोलकाता ब्यूरो - सुशांतो बनर्जी
चेन्नई ब्यूरो - कुमार देवेश
देहरादून ब्यूरो - पूजा बिष्ट
हैदराबाद ब्यूरो - इरफान
अहमदाबाद ब्यूरो - मोहित जडेजा
गुवाहाटी ब्यूरो - देवास्वरूप बरूआ
विधि सलाहकार - संतोष शुक्ल (अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ बेच)
ग्राफिक्स एवं डिजाइन - बसंत चौहान

कार्यालय: डी– 1/132, विराज खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ 226010 मोबाइल: 9415020028
ईमेल – uridmedia24@gmail.com

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी
द्वारा स्वास्तिक प्रिन्टिंग प्रेस 27 माई की बगिया बड़ा
चांदगंज लखनऊ उ0 प्र0– 24 से मुद्रित
डी–1/132, विराज खण्ड, गोमती नगर लखनऊ,
यू0पी0–226010 से प्रकाशित

उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।

प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के हैं इससे
सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

विषय सूची

महात्मा की अन्तरात्मा रो पड़ी, "जब सुभाष के सैनिक लुटेरों के सरदार बने"............................ 05

क्या जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू सरकार का रिकॉर्ड तोड़ेगी मोदी सरकार ? 19

भारत जोड़ों यात्रा... 22

2014 से अब तक कितना बदला संविधान 29

अमरीका की आर्थिक मंदी भारत के लिए खतरे का संकेत ? 36

किस कंपनी में कितनी छंटनी 39

डा0 अनिल चतुर्वेदी

स्मृतियों में

जन्म तिथि- 01 जुलाई 1963 - 07 अक्टूबर 2022

महात्मा की अन्तरात्मा रो पड़ी, "जब सुभाष के सैनिक लुटेरों के सरदार बने"

– डा0 अनिल चतुर्वेदी

आज़ाद हिन्द फ़ौज के कैप्टन निंबालकर, जिन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। उनसे महात्मा गाँधी ने बोला "मेरा सुभाष चंद्र बोस के साथ तीव्र मतभेद था, फिर भी उनकी देशभक्ति, उनके साहस और उनके सूझ बुझ की मैं सदा सराहना करता आया हूँ"।

सुभाष के मन में गाँधी के प्रति इतना सम्मान था कि जापान में 26 जनवरी को आज़ाद हिन्द फ़ौज की सलामी लेते हुए राष्ट्रीय तिरंगे को फहराया तो सामने महात्मा गाँधी की बड़ी सी तस्वीर रखी और कहा "आप राष्ट्र पिता हैं, पूरे देश के पिता" और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी "फादरऑफ़आलनेशन"। गाँधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के साहस का जिक्र करते हुए कहा "उन्होंने हिन्दुस्तान के सभी प्रांतों और सारे धर्मों के लोगों की एक फ़ौज तैयार की और अपना शानदार उदाहरण प्रस्तुत करके उन्होंने लोगों में स्वैच्छिक अनुशासन और आज्ञाकारिता की भावना भरी। उनकी छोटी सी सेना के लिए मौजूदा ज़माने में सबसे ताकतवर साम्राज्य से लड़ना कोई मामूली बात नहीं थी।" नेता जी ने अपने सैनिकों को सलाह दी थी कि वे हिन्दुस्तान की भीतर की लड़ाई गाँधी जी की सलाह से चलायें क्योकि उस लड़ाई की कल्पना गाँधी जी की है और हिन्दुस्तान के बाहर की लड़ाई की मेरी।

इसी बीच हिन्दुस्तान के टुकड़े करने का ऐलान हो गया। पूरे देश में एक हलचल भी थी और संशय भी था कि आगे क्या होगा? आज़ाद हिन्द के कुछ सदस्यों ने महात्मा गाँधी से पूछा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और हमारा क्या होगा? महात्मा गाँधी ने जवाब देते हुए कहा कि "आप फौजियों के लिए मेरा जवाब यही है कि आप लोग न तो मौजूदा फ़ौज में लिए जाने की उम्मीद करे और न हिन्दुस्तान के दो हिस्सों में से किसी में अपना अलग से फौजी दस्ता बनाएँ। मैं समझता हूँ कि कम से कम कुछ समय के लिए यह चीज़ अव्यावहारिक है। सबसे अच्छा तो यह होगा कि ज़मीन के किसी एक टुकड़े पर बस जाएँ और अपनी तलवारों को हलों में बदल दें, ज़मीन पर एक साथ काम करें और भूखों मरते करोड़ों देशवासियों के लिए ज्यादा अनाज पैदा करें।"

लेकिन विडम्बना यह हुई कि कश्मीर प्रांत पर कबाइलियों द्वारा हमला कर दिया गया। उनमें पाकिस्तानी सेना ने कबाइलियों का साथ दिया और इन कबाइलियों का नेतृत्व मेजर खुर्शीदअनवर कर रहे थे। उनके साथ सुभाष बाबू के खासमखास जो उनके साथ सदा रहा करते थे जमात क्यानी। यह दोनों अफसर आज़ाद हिन्द फौज और सुभाष के खास थे। मेजर खुर्शीदअनवर के नेतृत्व में कबाइलीबारामुला तक आ गये। श्रीनगर केवल 35 मील दूर था। अगर वो तुरंत निकलते तो अगले दिन श्रीनगर उनके हाथ में आ गया होता लेकिन कबाइलियों और पाकिस्तानियों का उद्देश केवल कश्मीर जीतना ही नहीं था बल्कि लालचवश कश्मीर को लूटना भी था। सरकार शौकत हयात खान ने अपनी किताब **"नेशनहैज़लास्टइटसोल"** में लिखा है कि मेजर खुर्शीदअनवर ने जो राज्य के खजाने में मिला 3 लाख रुपया था उनमें और कबाइलियों में अपने हक़ को लेकर लड़ाई हो गई। जब यह मुद्दा हल हो गया तो कबाइलियों जिन्हे समय का कोई बोध नहीं था उन्होने कहा ईद के बाद आगे बढ़ेंगे। उन्होने स्थानीय लोगों को लूटना और बारामुला की एक कान्वेंट स्कूल की ननों की लाकेट एवं बालियाँ काटनी शुरू कर दी और पठानों ने बाज़ारों को लूटना शुरू कर दिया। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने आकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब यह खबर महात्मा गांधी को मिली कि आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों की कश्मीर हमलो में भूमिका थी और वो पहले से ही हमलावरों से मिले हुये थे तो महात्मा गांधी अपनी आवाज़ इन शब्दों के साथ उन्हें पहुचाने की कोशिश कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि सुभाष जैसे देशभक्त के सैनिक आज लुटेरों के सरदार बन गये है अगर मेरी आवाज़ सुभाष के उन सैनिकों तक पहुचती है तो मैं उसने पूछना चाहता हूँ कि सुभाष बाबू का नाम क्यो बदनाम कर रहे है गांधी ने कहा कि आज सुभाष बाबू होते तो कश्मीर हमले में सैनिकों के इस लुटेरे रुख को देखते तो उनको कितनी पीड़ा होती। इसका सहज अनुमान कोई भी लगा सकता है। सुभाष बाबू अपने सैनिकों की इन हिंसा को देखते तो महात्मा गांधी के अहिंसा का रुख ही अपनाते।

महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र बोस भारत माता के बेमिसाल पुत्र है। दोनों ही अपनी माता को बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए आजीवन जुझते रहे। दोनों के वैचारिक मतभेद थे लेकिन लक्ष्य एक था।

जब सुभाष की गाँधी ब्रिगेड ने मणिपुर पर कब्ज़ा किया

सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी पर सवार होकर जर्मनी से जापान पहुंचे। जापान में रासबिहारीबोस तथा भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय स्वाधीनता संग और आज़ाद हिन्द फ़ौज के बीच की गहरी खाई को सुभाष चंद्र बोस ने बड़ी कुशलता से समाप्त किया और इनमें सभी जातियां, धर्मों और वर्गों के लोग थे, सभी देशभक्त थे और फ़ौज में झांसी की रानी रेजिमेंट में महिलायें भी 1000 की संख्या में भर्ती की गयी थी। सुभाष चंद्र बोस ने हिन्द फ़ौज को 4बिग्रेट में बाँटा। गाँधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, और सुभाष ब्रिगेड ।

इससे पता चलता है कि सुभाष व गाँधी में मतभेदों के बाबजूद गाँधी एवं नेहरू को कितना मान देते थे। सुभाष चंद्र बोस को राजबिहारीबोस ने सर्वप्रथम "नेताजी" कह कर सम्बोधित किया। अब सुभाष बोसनेताजी और आज़ाद हिन्द फ़ौज के कमांडर इन चीफ दोनों बन गए और उनके बाद वह हमेशा कमांडर की वर्दी में रहने लगे। भला कमांडर की वर्दी में रहने वाले सुभाष चंद्र बोस और खादी की लंगोटी में रहने वाले महात्मा गाँधी में एक दूसरे के प्रति साम्यता उस युग के लिए आश्चर्य का विषय थी। आज़ाद हिन्द फ़ौज की सेना जापानी फील्डमार्शलतेटाची के नेतृत्व में मणिपुर पर आक्रामक कर दिया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भयंकर रक्तपात हुआ। हिन्द फ़ौज और अंग्रेजी सेना के बीच खून की नदियां बही। विडंबना ही कही जायेगी कि गाँधी ब्रिगेड ने ही इम्फाल में आज़ाजहिन्द फ़ौज का ध्वज फहराया। जून 1944 में 600 आज़ाद हिन्द फ़ौज के सेनानियों ने 300 ब्रिटिश सिपाहियों से जम कर टक्कर ली। 31 दिसंबर 1944 ब्रिटिश सेना ने वर्मा का कूच किया। वर्मा की रक्षा करने में आज़ाद हिन्द फ़ौज तो लगी रही पर जापानी धोखा दे कर भाग गए। जापानी सैनिकों ने वर्मा से भागते वक़्त वर्मा में भीषण रक्तपात किया। वर्मा की भीषण बर्बादी जापानियों के हाथ देखकर नेता जी का मन आवश्य रोया था। वर्मा की जगह भारत को रख कर देखने के बाद उनका भावुक मन इतना

दुखी हुआ होगा, यह वर्णन नहीं किया जा सकता है। जापानी धोखा देकर चले गए थे। जापान के हथियार डालते ही अंग्रेजी हुकूमत ने आज़ाद हिन्द फ़ौज के कमांडर और सिपाहियों को बंदी बना लिया। सुभाष चंद्र बोस ने जापानियों से कहा कि वह उन्हें रूस भेज दें पर जापानियों ने मना कर दिया। लेकिन कैप्टन तेटाची ने सुभाष की मदद की और एक निजी विमान का प्रबंध कर दिया। सुभाष के साथ उनके सहयोगी हबीबुर्रहमान थे। अचनाक23 अगस्त 1945 को खबर आयी कि हॉर्मास के निकट तोहोमे पहाड़ी पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अत्यधिक जल जाने के कारण बोस ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। गाँधी जी हमेशा से अहिंसा को ही मानव मात्र का साध्य बताते हुए कहा कि उनकी नीति सत्य और अहिंसा की नीति है। उनका कहना था कि घृणा को प्यार में नहीं बदला जा सकता। जो लोग हिंसा में विश्वास रखते है वह अपने दुश्मन को मार डालने और उनकी सम्पति को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसका नतीजा यह होगा कि घृणा और गहरी होती जायेगी। घृणा, घृणा को जन्म देगी और दोनों तरफ से प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठेगी। उन्होंने सुभाष चंदबोस से कहा था कि "यदि तुम भारत को अपने तरीके से स्वतंत्रता दिला देते हो तो सबसे पहला व्यक्ति मैं आऊंगा तुम्हारे स्वागत के लिए. भले ही साधन की सुचिता में मेरा विरोध है तुमसे, पर मुझे विश्वास है कि इसमें सफलता नहीं मिलने वाली"। इस तरह गाँधी और सुभाष के बीच विचारात्मक द्वंदता थी जहाँ सुभाष भारत की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ छोड़ सकते थे, सत्य, अहिंसा ही नहीं अपना जीवन भी। भले ही इसके लिए बेनिटोमुसोलिनी, एडोल्फहिटलर या जोसेफस्टालिन से मदद ली जाए। इसके विपरीत गाँधी जी अपने साधन की सुचिता पर बल देते थे। जहाँ दुश्मन के लिए भी मन में करुणा हो और उनके प्रति मन अहिंसक रहता हो।

सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन काल में ही वर्मा में हिंसा और बर्बादी का आलम देख चुके थे। उनका विशवास था कि धुरी राष्ट्रों (जापान , इटली और जर्मनी) की जीत अवश्य होगी। मित्र राष्ट्र हार जाएंगे। शायद जापानियों द्वारा उन्हें खटारा विमान दिया गया था वह सचमुच एक भोले बालक की तरह धुरी राष्ट्रों के षड़यंत्र के शिकार बन गए। उनके द्वारा आजाद हिन्द के फ़ौज के सैनिक भी जो भारत माता की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार थे वह आपस में बटकर एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक कार्यवाही की। बोस के साथ रहने वाले सैनिकों ने ही कश्मीर में कबाइलियों का नेतृत्व किया फिर वर्मा में लूटपाट की पुनरावृत्ति की और पूँछ, बारामुला आदि क्षेत्रों में अपने ही देशवासियों को लुटा। यहाँ पर गाँधी का अंदेशा सही प्रतीत होता है कि हिंसा से हिंसा की ही उपज होगी। जो हम बोयेंगे वही काटेंगे। यह आज के समकालीन परिदृश्य में भी सही जान पड़ रहा है कि किसी भी समस्या का हल हिंसा द्वारा नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ भारत देश आज़ाद हुआ और गाँधी को इस सफलता का श्रेय मिला पर प्रश्न उठता है कि क्या गाँधी भी सफल रहे ? जिन्ना के इस व्यक्त्व पर कि "या तो विभाजन होगा या विनाश होगा...." और अंत में विनाशकारी विभाजन हुआ.... गाँधी के लाख प्रयासों के बाद भी नहीं रुका। तो क्या महात्मा गाँधी भी असफल रहे ? लेकिन इसे इस तरह समझा जा सकता है कि जिस प्रकार मनुष्य को हिंसा से हटाने में महात्मा बुद्ध तथा ईसा मसी असफल रहे परन्तु लोग इन्हे सदा ऐसे व्यक्ति की तरह याद करेंगे, जिसने अपने जीवन को आने वाले अनन्त युगों के लिए नसीहत बना दिया।

क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जब तीन बार मर के हुए जिंदा

हिटलर ने चिंतित मुद्रा में कहा "आपकी मदद को तैयार हूँ । सुभाष ने इसके जवाब में कहा कि मैं शीघ्र ही भारतीय सेना के नाम अपना सन्देश प्रसारित करूँगा। मैं उनके समक्ष स्थिति की वास्तविकता रखते हुए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध न करने की अपील करूँगा। आप विश्वास रखिये कि वह सैनिक हमारी बात अवश्य मान जायेंगे।

क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस भारतीय जनमानस में एक किवदंती के रूप में जाने जाते हैं। वह एक क्रांतिकारी नेता, सक्षम प्रशासक, देशभक्त एवं राबिनहुड की चरित्र की तरह जनमानस में व्याप्त है। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस गुप्त रूप से जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में ढेड़ साल के संघर्ष के बाद 29 मई 1942 को बर्लिन में हिटलर से मुलाकात हुई। उनका मानना था कि यही वह व्यक्ति है जो भारत को अग्रेंजी साम्राज्यवाद के चंगुल से छुड़ा सकता है। उन्होंने भारतीयों को दासता से मुक्ति दिलाने के लिए हिटलर से सहयोग की मांग की। हिटलर ने चिंतित मुद्रा में कहा "आपकी मदद को तैयार हूँ परन्तु भारतीय सेना का 10वां ब्रिगेड लीबिया में हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। सुभाष ने इसके जवाब में कहा कि मैं शीघ्र ही भारतीय सेना के नाम अपना सन्देश प्रसारित करूँगा। मैं उनके समक्ष स्थिति की वास्तविकता रखते हुए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध न करने की अपील करूँगा। आप विश्वास रखिये कि वह सैनिक हमारी बात अवश्य मान जायेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर के समक्ष तीन प्रस्ताव रखे-

(1) उन्हें जर्मन सरकार बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश सरकार विरोधी भाषण देने की स्वतंत्रता दे, जिससे भारत तक उनका सन्देश पहुंच सके।

(2) भारत के युद्धबंदियों को सरकार जर्मनी में आजाद हिन्द फ़ौज में भाग लेने की अनुमति दे।

(3) जर्मनी, जापान और इटली तीनों समय आने पर भारत की स्वाधीनता के समर्थन में घोषणा कर दें।"

पहली मृत्यु-

उपरोक्त तीनों प्रस्ताव में प्रथम दो पर इटली और जर्मनी ने अपनी सहमति दी। धूरी शक्तियों के समर्थन में सुभाष चंद्र बोस का आना ब्रिटिश सरकार को अच्छा नहीं लगा। ब्रिटिश सरकार ने एक साजिश के तहत एजेंसियों के माध्यम से मार्च 1942 को दुनिया भर में खबर फैला दी कि टोकियो में एक महत्वपूर्ण सम्मलेन में भाग लेने जाते वक़्त उनकी(सुभाष चंद्र बोस) की मृत्यु हो गयी। पूरे भारत में यह समाचार फ़ैल गया। महात्मा गाँधी ने भी बोस की माँ को एक तार भेजा........ "सम्पूर्ण राष्ट्र अपने और आप के वीर पुत्र की मृत्यु पर आपके साथ शोक मगन है। मैं आपके दु:ख में पूरी तरह शरीक हूँ। ईश्वर आपको इस अप्रत्याशित क्षति को सहन करने का साहस दें।"

लेकिन दूसरे ही दिन सूचना मिली कि यह खबर गलत है। महात्मा गाँधी ने तुरंत उनकी माँ प्रभावतीबोस को तार किया कि "भगवान् का लाख लाख धन्यवाद कि जिस समाचार को बिलकुल प्रामाणिक कहा जा रहा था वह गलत साबित हुआ। आपको और राष्ट्र को हमारी बधाई" . पत्रकार लुइफिशर के मन में यह प्रश्न उठा कि सुभाष की मृत्यु पर गाँधी जी को शोक करना उचित है ? गाँधी ने

इसका जवाब देते हुए कहा कि "बोस को मैं देशभक्तों का सिरमौर्य मानता हूँ। वे गुमराह हो सकते है मेरे और उनके विचार अक्सर भिन्न रहे हैं। फिर भी मेरा उनसे(बोस) पुत्रवत नाता है। इसलिए शोक करना कोई अनुचित है।" उन्होंने फिशर को निरुत्तर करते हुए कहा कि ब्रिटिश शासन में भी फांसीवाद के प्रबल तत्व महजूद है। हमेजर्मनी, इटली और जापान से प्रजातंत्र के लिए लड़ने को कहा जाता है। लेकिन हम खुद गुलाम है तब भला हम प्रजतन्त्र बचाने के लिए कैसे लड़ सकते हैं।

दूसरी मृत्यु-

दूसरी बार 23 अगस्त 1945 को जापान के टोकियोन्यूज़ एजेंसी ने भारत के लिए फिर एक अत्यंत हृदय विदारक न्यूज़ प्रसारित की जिसमे आजाद हिन्द फ़ौज के प्रमुख सुभाष चंद्र बोस अपने सहायक हबीबुर रहमान के साथ बैंकाक से टोकियो की विमान यात्रा कर रहे थे। अचानक विमान में आग लग गयी और वह फारमोसा के निकल दुर्घटना ग्रस्त हो गए। इस दुर्घटना में अत्यधिक जल जाने के कारण नेता जी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गयी। इस समाचार से सभी एक बार फिर भौचक रह गए। महात्मा गाँधी का मन भी इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। पिछली बार की तरह अब भी सुभाष चंद्र बोस अचानक प्रकट हो जायेंगे। महात्मा गाँधी को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर राजकुमारी अमृत कौर ने दी। पर उन्हें इस समाचार पर पूरा एतबार नहीं था। जब सुभाष के भतीजे अमिय नाथ बोस ने गाँधी जी से पूछा कि वह चाचा सुभाष चंद्र बोस का श्राद्ध करे या न करें, तो गाँधी जी ने कहा मैंने तो इस खंजर को संदेह की निगाह से देखा है, अगर तुम्हे भी संदेह हो तो ऐसी घोषणा कर दो और संस्कार मत करो।

10 जनवरी 1946 को महत्मा गाँधी ने गुहाटी में यह दोहराया कि सुभाष बाबू की मृत्यु नहीं हुई है बल्कि वह कहीं छिपे हुए हैं। 8 महीने तक महात्मा गाँधी इसी आशा में रहे कि सुभाष बाबू शायद जीवित हो पर जब उस विमान में सुभाष के सहयोगी हबीबुर रहमान उनसे मिले और उन्होंने गाँधी जी को सुभाष चंद्र बोस की जली हुई काली घड़ी दिखाई और उनकी मृत्यु अपनी आखों के सामने होने की पुष्टि की तब महात्मा गाँधी ने 30 मार्च को अपने पत्र हरिजन में एक लेख लिखा "क्या नेता जी जिन्दा है ?" गाँधी जी की तरह सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस ने कभी नहीं माना कि सुभष की मृत्यु हुई है। हमेशा इसे एक साजिश और षड़यंत्र का हिस्सा ही मानते चले आये। वह सुभाष के राजनीतिक विरोधियों के प्रति हमेशा सशंकित रहे और इस तरह से सुभाष के दूसरे मृत्यु का समाचार भी विवादों से घिर गया।

तीसरी मृत्यु-

बाद में अयोध्या में गुमनामी बाबा को लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के रूप में देखा। गुमनामी बाबा इस इलाके में तकरीबन 15 साल रहे। वे 1970 के दशक में फैजाबाद

पहुंचे थे। शुरुआत में वे अयोध्या की लालकोठी में किरायेदार के रूप में रहा करते थे और इसके बाद कुछ समय प्रदेश के बस्ती शहर में भी बिताया लेकिन यहां लंबे समय तक उनका मन नहीं लगा और वे वापस अयोध्या लौट आए। यहां वे पंडित रामकिशोर पंडा के घर रहने लगे। कुछ सालों बाद ही उन्होंने यह जगह भी बदल दी। उनका अगला ठिकाना अयोध्या सब्जी मंडी के बीचोबीच स्थित लखनऊवाहाता रहा। इन सारी जगहों पर वे बेहद गुप्त तरीके से रहे। 16 सितंबर, 1985 को सिविल लाइंस में स्थित 'राम भवन' में गुमनामी बाबा की मौत होती है और उसके दो दिन बाद बड़ी गोपनीयता से इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है।

यह रोचक और तथ्यपूर्ण है कि आज भी तीनों मृत्यु की आधिकारिक घोषणा नहीं जा सकी है। सुभाष चंद्र बोस किवदंती के रूप में आज भी विद्यमान है। उनके त्याग, बलिदान और देशभक्ति का कोई सानी नहीं है।

पटेल की साजिश से सुभाष ने कांग्रेस छोड़ा

जवाहर लाल नेहरू का अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा था। अगले अध्यक्ष के नाम पर चर्चा होनी थी। जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल में ही सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया था। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन होना था। जब चर्चा हो रही थी वहां पटेल, नेहरू, आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद आदि बैठे थे। वहां महात्मा गाँधी ने अपना दृष्टिकोण रखा कि सुभाष बाबू को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए यह मेरा मत है। कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बना दिया। सुभाष चंद्र बोस उस समय वियना(आस्ट्रिया) में थे। वापस लौटने पर हरिपुरा में 19 फरवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। चुकि यह 51वां अधिवेशन था तो इसके लिए 51 द्वार बनाये गए, 51 राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए और 51 सफ़ेद बैलों से जुटे हुए रथ पर सुभाष चंद्र बोस की यात्रा निकाली गयी और जवाहर लाल नेहरू ने नए अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया। इसी 19 फरवरी 1938 को हरिपुरा अधिवेशन में सरदार पटेल ने अपने भाषण में कांग्रेसी, समाजवादियों के विषय में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। चूकी उस समय कांग्रेस के रेजोल्यूशन में यूनाइटेड प्रोविन्स और मंत्रीमंडल के इस्तीफे का सवाल था और कानपुर में टेक्सटाइल मजदूर की हड़ताल पर टिप्पणी करते हुए पटेल ने जानबूझ कर और उत्तेजक भाषण शुरू किया। केवल हड़ताल के अलावा सोशलिस्ट कांग्रेस के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। चेतावनी देते हुए कहा कि आप जितना चाहिए रेजोल्यूशनलाईये। हम आपका सामना करने को तैयार है। आप को हम 2 साल से बर्दाश्त कर रहे है लेकिन अब समय आ गया है कि हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह की टिप्पणी का विरोध अधिवेशन में आये हुए सदस्यों द्वारा किया गया। इससे अधिवेशन में उपस्थित सभी लोग सरदार पटेल के मन में सुभाष चंद्र बोस और उनके सहयोगियों के प्रति दुर्भावना भाँप गए। यहाँ तक की 20 फरवरी को महात्मा गाँधी ने पटेल को लिखा कि "तुम्हारा भाषण बहुत गर्म था। यदि तुम्हे अपनी भूल महसूस हो तो तुम सुभाष की विशेष अनुमति लेकर

मंच पर जाकर उनके आँसू पोछना और उन्हें हँसाना। हम जैसे को तैसा वाला व्यवहार नहीं कर सकते। बलवान का भूषन क्षमा है।" यह सच था कि 51वां कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए सरकार पटेल, राजेंद्र बाबू, जमुना लाल बजाज भी इच्छुक थे। पर गाँधी ने पटेल से सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनने देने की अपील की थी। महात्मा गाँधी ने समाजवादियों का समर्थन करते हुए तथा राजेंद्र बाबू, पटेल आदि का विरोध करते हुए कहा कि जो समाजवादी कांग्रेस के सिद्धांतों में विश्वास रखते है, उन्हें अपनी समाजवादी विचारधारा के कारण कांग्रेस से अलग नहीं किया जा सकता। पंडित नेहरू और श्री सुभाष चंदबोस भी समाजवादी हैं। यही से सुभाष और पटेल के बीच वैमनस्यता का सूत्रपात हो चूका था। जब 1939 में त्रिपुरी(जबलपुर) कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस को पुन अध्यक्ष चुन लिया गया लेकिन गाँधी जी इस निर्णय से खुश नहीं थे। उन्हें सुभाष चंद्र बोस से कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी परन्तु कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी ताकतों जिसका नेतृत्व पटेल रह रहे थे उन्होंने गाँधी को मना कर अपने पक्ष में कर कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। गाँधी ने लिखा है कि "तुम्हारा यह मानना कि किसी ने मुझे तुम्हारे विरुद्ध खड़ा किया है यह तुम्हारी भूल होगी। यदि तुम ऐसा सोचते हो कि पुराने लोगों में कोई व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा दुश्मन है तो तुम गलती कर रहे हो।"

गाँधी ने लिखा है कि "तुम्हारा यह मानना कि किसी ने मुझे तुम्हारे विरुद्ध खड़ा किया है यह तुम्हारी भूल होगी। यदि तुम ऐसा सोचते हो कि पुराने लोगों में कोई व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा दुश्मन है तो तुम गलती कर रहे हो।"

सुभाष चंद्र बोस के मन में यह बात घर कर गयी थी कि गाँधी और उनके बीच मतभेद करने का प्रयत्न त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन से ही किये जा रहे थे। त्रिपुरी में पुराने महारथी बड़ी चतुराई से खुद तो सामने से हट गए और मुझे आप से भिड़ा दिया। मेरे और आप के बीच कोई झगड़ा था ही नहीं। उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि उन लोगों की महाविजय हुई और मेरी पराजय। सच तो यह है कि वह न उनकी विजय थी और न मेरी पराजय। वह तो आपकी विजय थी लेकिन वह एक सर्वनाशी विजय थी। किसी हद तक जाकर प्रतिष्ठा की बलि चढ़ा कर प्राप्त की गयी विजय थी। उनका इशारा स्पष्ट तौर पर सरदार पटेल पर था। उन्होंने जवाहर लाल नेहरू को लिखा। जबकि महात्मा जी और मेरे बीच कोई अविश्वाश था ही नहीं तो गाँधी को मेरे विरुद्ध करना इन लोगों का कहाँ तक उचित था। अगर यह पुराने योद्धा मुझे से झगड़ना चाहते थे तो स्पष्ट रूप में वह सामने क्यों नहीं आये ? महात्मा गाँधी को इस बीच में क्यों खींचा ? बेशक यह चालाकी भरा कदम था। क्या सरदार पटेल को यह घोषित करना उचित था कि मेरी पुनः अध्यक्ष बनना देश हित में नहीं होगा? सरदार पटेल और अन्य लोग बड़ी चतुराई से आप से कार्य करा लेते हैं मेरी इच्छा के विरुद्ध कृपलानी जी को लाया गया। यदि कांग्रेस कार्यालय की दशा बिगड़ी है तो उसका उत्तरदायित्व कृपलानी पर है न कि मुझ पर।

यहाँ उल्लेखनीय है कि सुभाष चंद्र बोस को आभास था कि उनके और गाँधी के बीच कोई साजिश रची जा रही है। उनका इशारा स्पष्ट रूप से सरदार पटेल की और था। चूकी विठल भाई पटेल की सम्पति को लेकर सरदार बल्ल्भ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस में गहरा विवाद हुआ था। आपसी मुक़दमे, जिसमे सरदार पटेल की जीत हुई थी। पुनः सुभाष चंद्र बोस उच्चतम न्यायालय गए

लेकिन यहाँ भी सरदार पटेल की जीत दर्ज़ हुई। जिससे इन दोनों में कटुता बढ़ती ही गयी। महात्मा गाँधी जब कांग्रेस अधिवेशन के लिए 27अप्रैल 1939 को कलकत्ता गए तो साथ में सरदार पटेल को अपने साथ नहीं ले गये। ट्रेन में यात्रा क़रने के दरम्यान खड़गपुर और कलकत्ता के बीच समाचार पत्र स्टेट्समैन के प्रतिनिधि के सवाल के जवाब में महात्मा गाँधी ने इस तथ्य को स्वीकार किया। पत्रकार का प्रश्न था कि आपने सरदार पटेल को कलकत्ता न आने की सलाह दी है इसलिए आप शांति मिशन पर कलकत्ता आये हैं ? महात्मा गाँधी का उत्तर था- हाँ, सरदार पटेल के न आने का कारण यह था कि उनका कलकत्ता से दूर रहना देश के सर्वोत्तम हित में था। पत्रकार के इस प्रश्न पर- सुना जाता है कि सुभाष अवांछित व्यक्ति है। महात्मा गाँधी ने जवाब दिया मैंने कही नहीं सुना मेरे पास ऐसा विशवास करने का कोई कारण नहीं है कि सुभाष अवांछित व्यक्ति है। महात्मा गाँधी ने पटेल की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा की बहुत से लोगों के दिल में ऐसा है कि सरदार ठीक काम नहीं करते तथा सरदार पटेल की साजिश ने सुभाष चंद्र बोस को अलग कर दिया। यदि सुभाष के मन में यह भावना है तो उन्हें यह बात पटेल से साफ़ साफ़ बात कर लेनी चाहिये, किसी भी अहिंसावादी का शाश्वत धर्म यही है। इसलिए मैं जानबूझ कर अन्याय करने वाले का साथ नहीं दूंगा लेकिन आपके दिल में यही सरदार के प्रति कुछ है तो आपको जाकर उनसे ही पूछना चाहिए। सुभाष बाबू ने इस्तीफा देते समय कहा की मुझे अत्यंत खेद है कि त्रिपुरी अधिवेशन के समय कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा करने में मैं असमर्थ रहा हूँ और साथ में मैं महात्मा के सुझाव पर अमल नहीं कर पाया इसलिए मैं परिपक्व सोच व सहयोग के साथ मैं आपके हाथों में अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ और इस्तीफे के दूसरे दिन फॉरवर्डब्लॉक के नाम से एक पार्टी बनाई जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने और उपाध्यक्ष पंजाब के सरकार सार्दुल सिंह बने।

इतिहास में सरदार पटेल की छवि एक कुशल प्रशासक की रही है। किन्तु इनके साथ साथ इन की छवि हिंदूवादी एवं अपने विरोधियों के प्रति दुर्भावना व द्वेष से परिपूर्ण भी रही है। वे गाँधी के सच्चे अहिंसक सिपाही कभी नहीं बन पाए।

जायदाद को लेकर सुभाष और सरदार पटेल के बीच हुई मुकदमेबाज़ी

सुभाष और पटेल के बीच की खाई कांग्रेस में बढ़ती गयी। उनके बीच की दूरी तब और बढ़ गयी जब पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल के सम्पत्ति विवाद को लेकर कोर्ट जाना पड़ा तो इनके बीच कटुता चरम पर पहुँच गयी। वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल का जन्म 27 सितम्बर 1873 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। इनके पिता का नाम झवेरभाई पटेल एवं मां का नाम लाडबा देवी पटेल था। इनके पांच बेटों में विट्ठल भाई पटेल तीसरे नंबर के थे। इनकी शिक्षा दीक्षा बॉम्बे और नडियाद

में हुई थी। वल्लभ भाई पटेल इनसे 2 वर्ष छोटे थे। इनके पिता स्वामी नाथ नारायण सम्प्रदाय के वैष्णव भक्त थे। विट्ठल भाई पटेल ने लन्दन में भी शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर बने। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद और बॉम्बे में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। विट्ठल भाई पटेल गाँधी जी के प्रबल आलोचक थे। विट्ठल भाई पटेल 1922 में कांग्रेस छोड़ कर स्वराज पार्टी में शामिल हो गए थे। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी चुने गये। उनके तीखे भाषण और लेख पार्लियामेंट में मुख्य केन्द्र बिंदु होते थे।
विट्ठल भाई पटेल ने अपने राजनीति के अंतिम दिनों में अमेरिका और यूरोप की यात्रा शुरू की। वह न्यूयॉर्क, बोस्टन, फ्रांसिस्को, लन्दन, जनेवा आदि शहरों में भ्रमण किया। न्यूयॉर्क, बोस्टन और फ्रांसिस्को के मेयर ने उनका स्वागत किया। यहाँ तक कि अमेरिका राज्य पेन्सिलवेनिया और मेरीलैंडके गवर्नर ने सरकारी समारोह में उनका स्वागत किया। विट्ठल भाई पटेल को ब्रिटिश सरकार द्वारा आयरलैंड के बीच आर्बिट्रेटर भी नियुक्त किया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में थे। वहां उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई। उन दोनों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए लिखा कि महात्मा गाँधी एक असफल नेता हैं। भारत को उनके बताये रास्ता पर चलने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष द्वारा भारत को आज़ादी दिलाने की कसम खाई। उल्लेखनीय है कि उनके जिनेवा में मृत्यु के बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक वसीयत को सामने रखा। वसीयत को पढ़ने के बाद पता चला कि विट्ठल भाई पटेल ने अपनी जायदाद का तीन बटा चार हिस्सा सुभाष चंद्र बोस को दिया था जिसे वह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को अन्य देशो में प्रसारित करने के लिए उपयोग करेंगे और इसके साथ यह भी इच्छा जाहिर की थी कि हमारे मृतक शरीर को सुभाष बाबू को सौपा जाये जो यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि उनका शरीर बम्बईपंहुच जाये और उनकी समाधि बॉम्बे स्थित बाल गंगाधर तिलक की समाधि के बगल में बनाई जाये। जब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिखाए गये वसीयत को वल्लभ भाई पटेल ने देखा तो उन्होंने प्रश्नों की बौछार लगा दी और उस वसीयत को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह वसीयत उनके मृत्यु के समय उपस्थित डॉक्टर द्वारा सत्यापित नहीं है। दूसरा प्रश्न उठाया कि मूल वसीयत को कभी नहीं दिखाया गया। तीसरा प्रश्न था कि उस वसीयत में सभी गवाह बंगाली ही थे जबकि जिनेवा में कांग्रेस के आलावा और स्वतंत्रता सेनानी भी महजूद थे। चौथा प्रश्न इन्होने हस्ताक्षर में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया। यह विवाद एक साल तक उच्च न्यायालय में चला जिसमे पटेल की जीत हुई और उच्चम न्यायालय ने भी इस पर मुहर लगा दी और विट्ठल भाई पटेल की सम्पति को उनके क़ानूनी उत्तराधिकारियों को दिला दी गयी। वल्लभ भाई पटेल ने उनकी सारी सम्पति को विट्ठल भाई ट्रस्ट बना कर उसमे दे दिया।

जनमत संग्रह का विचार नेहरू ने नहीं बल्कि लॉर्डमाउन्टबेटन ने रखा था

कश्मीर के बारे में नेहरू के खिलाफ बहुत भ्रान्तियां है कि नेहरू जी जनमत संग्रह की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र गये। यह सर्वथा निराधार एवं असत्य है। परवेज़ दीवान द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में पेज नंबर 157 में इतिहारकार मिस्टर दास गुप्ता को उद्धृत करते हुये कहा गया है कि "पंडित नेहरू ने नहीं बल्कि लॉर्डमाउन्टबेटन ने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में जनमत संग्रह की बात उठाई थी। नेहरू जी ने इसका

कड़ा विरोध किया था। इतना ही नहीं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंटएटली ने फ़ोन करके नेहरू को वार्निंग भी दी थी।

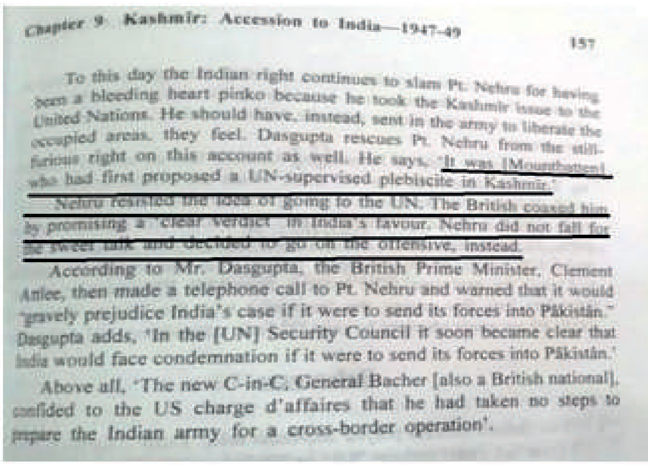

Chapter 9 Kashmir: Accession to India—1947-49 157

To this day the Indian right continues to slam Pt. Nehru for having been a bleeding heart pinko because he took the Kashmir issue to the United Nations. He should have, instead, sent in the army to liberate the occupied areas, they feel. Dasgupta rescues Pt. Nehru from the still-furious right on this account as well. He says, 'It was [Mountbatten] who had first proposed a UN-supervised plebiscite in Kashmir.'

Nehru resisted the idea of going to the UN. The British coaxed him by promising a "clear verdict" in India's favour. Nehru did not fall for the sweet talk and decided to go on the offensive, instead.

According to Mr. Dasgupta, the British Prime Minister, Clement Attlee, then made a telephone call to Pt. Nehru and warned that it would "gravely prejudice India's case if it were to send its forces into Pâkistân." Dasgupta adds, 'In the [UN] Security Council it soon became clear that India would face condemnation if it were to send its forces into Pâkistân.'

Above all, 'The new C-in-C, General Bacher [also a British national], confided to the US charge d'affaires that he had taken no steps to prepare the Indian army for a cross-border operation'.

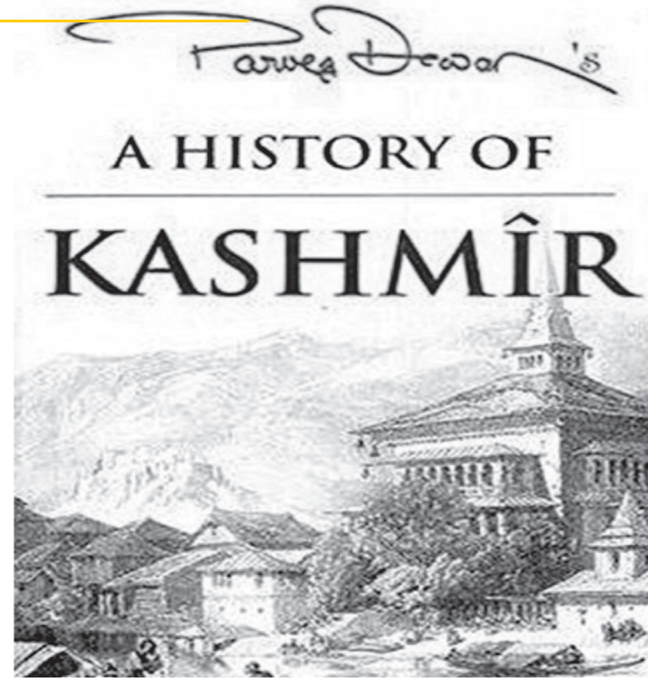

महात्मा गांधी की पहली और आखिरी कश्मीर यात्रा

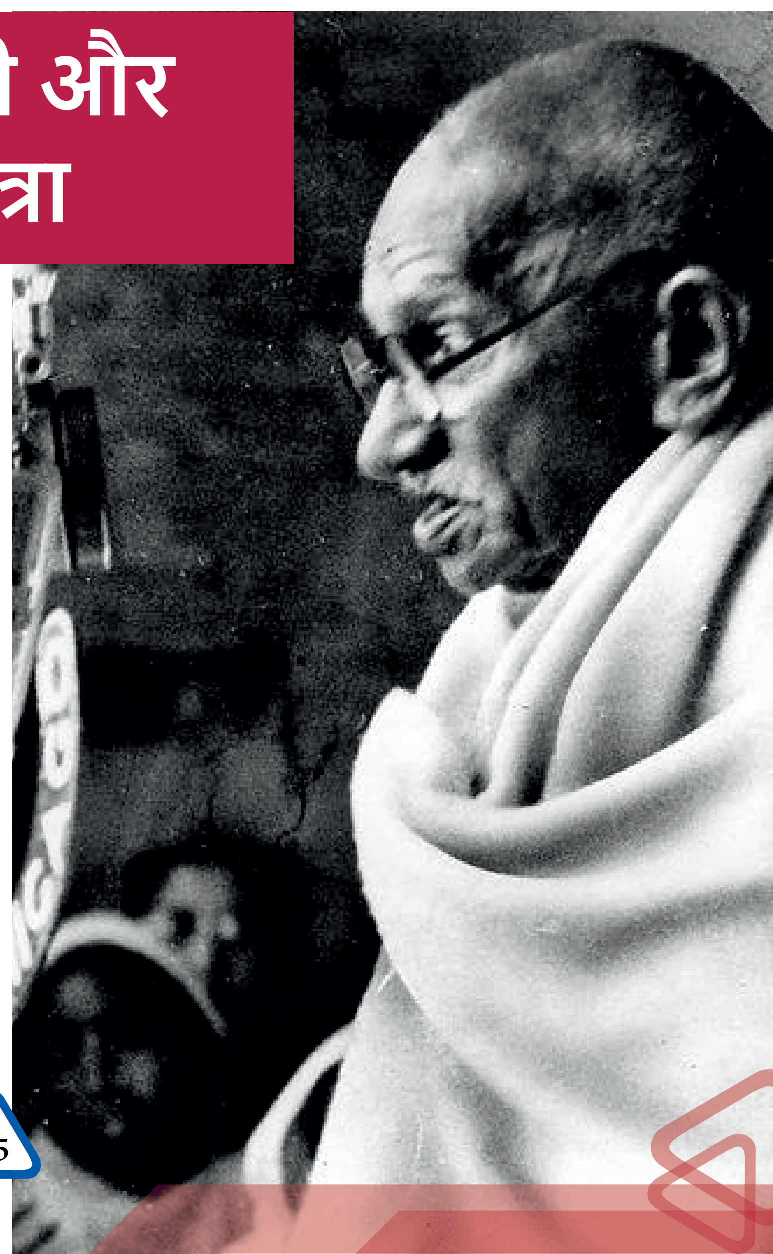

1 अगस्त 1947, जब कश्मीर में शेख अब्दुल्लाह को राजा हरी सिंह ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी रिहाई में देर होने लगी तो कश्मीर में एक अनिश्चितता का माहौल व्याप्त हो गया। नेहरू जी खुद कश्मीर जाना चाहते थे लेकिन गवर्नरलार्डमाउंटबेटन हालात की नाजुकता देखते हुए नेहरू जी को मना किया इससे और तनाव बढ़ सकता था। हरी सिंह भी नेहरू की यात्रा को लेकर काफी सशंकित थे। ऐसे में माउंटबेटन के आग्रह पर महात्मा गाँधी ने कश्मीर जाने का निर्णय लिया। गांधी श्रीनगर पहुंचे तो जनता ने उनके स्वागत में शहर को ऐसे सजाया जैसे कि दीवापली हो। महाराजा हरी सिंह की पत्नी तारा देवी सोने के थाल में दूध का गिलास लिए नंगे पाँव गाँधी का स्वागत करने पहुंची और गाँधी से कहा कि जब कोई महान संत हमारे यहाँ आता है तो यह परम्परा है कि हम दूध पीला कर उसका स्वागत करते है लेकिन गाँधी ने कहा कभी भी उस राजा का दूध स्वीकार नहीं कर सकता जिसकी प्रजा दुखी हो।

उन्होंने महाराजा की जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्लाह का अथिति स्वीकार किया और उनकी बेगम अकबर जहाँ को सहस और धीरज रखने को कहा। अकबर जहाँ भी महात्मा गाँधी की प्रार्थना सभा में शामिल हुई। इतना तय है कि गाँधी ने राजा से जनता की इच्छा का सम्मान करने और शेख अब्दुल्लाह को रिहा करने की मांग की। जम्मू में उन्होंने हिन्दू प्रतिनिधिमंडल से साफ़ कहा कि जनता के हाथ में यह तय करने की शक्ति होनी चाहिए कि वह किसके साथ जुड़ना चाहती है और इसके लिए शेख अब्दुल्लाह को रिहा करना बहुत जरुरी हैं। गाँधी की इस यात्रा से महाराजा पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा और जनता के बीच बेहद बदनाम रामचंद्र काक को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया जो कि भारत के हित में था। गाँधी की इस यात्रा का महत्त्व इस वजह से भी बढ़ जाता है कि इसी दौरान जिन्ना भी लगातार कश्मीर आने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने महाराजा को कई सन्देश भिजवाए लेकिन महाराजा ने बहुत विनम्रता से यह कहते हुए मना कर दिया कि वह अभी इस स्थिति में नहीं है कि एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के राज्य प्रमुख के स्वागत के लिए आवश्यक व्यवस्थायें कर सके और इस तरह गाँधी ने अपने जीवन की पहली और आख़री कश्मीर यात्रा की।

नेहरू पटेल विवाद क्यों ?

भाजपा के शासनकाल में नेहरू और पटेल के बीच एक बड़ी विवादित रेखा खींचने की कोशिश लगातार जारी है। आखिर इस विवाद के पीछे किसे फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। भाजपा समर्थक पटेल के कद को बढ़ाना चाहते हैं वो भी इस शर्त पर कि नेहरू को नीचा दिखाया जा सके। इसके पीछे नेहरू को नेता जी सुभाष के मृत्यु में, चाइना युद्ध में नेहरू की भूमिका, कश्मीर विवाद को यूएन में ले जाना इत्यादि नेहरू की देन मानते है और पटेल के पक्ष में तर्क देते है कि उन्होंने नेहरू से अलग देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए कार्य किया तथा नेहरू ने देश तोड़ने का काम किया और पटेल ने देश को एकसूत्र में पिरोया। इतिहास के पन्नो में भी नेहरू-पटेल-गाँधी के बीच दरार के कई किस्से मौजूद हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके बीच वैमनस्यता, कटुता व घृणा के भाव थे। उनके विचार समय समय पर आपस में टकराहट जरूर पैदा करते थे वह भी विचारों के माध्यम से लेकिन देश के निर्माण में दोनों सशक्त रूप से आपस में सहयोग भी करते थे।

इन दोनों का सही मूल्याकन इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में जाकर देखा जा सकता हैं। जहाँ नेहरूमोतीलाल जैसे बैरिस्टर के बेटे थे, उनकी शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई वही पटेल की पृष्ठभूमि एक मध्यम वर्ग परिवार से थी। मोतीलाल एक एथीस्ट थे (जो धर्म को नहीं मानते थे) वही पटेल के पिता जावेरी लाल पटेल स्वामीनाथ सम्प्रदाय के भक्त थे। वह 85 साल के उम्र में भी 30 किलोमीटर पैदल जाकर मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। जहाँ नेहरू पश्चिमी सभ्यता और विचारों से ओतप्रोत थे वही पटेल पूर्णतया भारतीय परम्परा के पोषक थे। नेहरू ने साम्यवाद, समाजवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद, लोकतंत्र आदि पाश्चात्य विचारों पर गहन अध्ययन किया था। वही पटेल भारतीय साहित्य व धर्म एवं कानून के ज्ञाता थे। नेहरू एक

प्रखर वक्ता थे, पटेल एक अच्छे प्रशासक। नेहरू की अंग्रेजी भाषा पर पकड़ अच्छी थी वह पटेल से कम उम्र के ऊर्जावान व्यक्ति थे। जहाँ नेहरू को भारत के गांव में जाकर भारतीय संस्कृति को देखना पड़ा वहीं पटेल का लालन पालन गांव के परिवेश में ही हुआ। वह भारत को अच्छी तरह से जानते थे। यह दोनों महात्मा गाँधी के संपर्क में आये जहाँ पटेल ने गाँधी को अपना गुरु माना वहीं गाँधी ने नेहरू के प्रति पुत्रवत प्रेम रखा। दोनों गांधी जी के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने कदम कदम पर गाँधी जी का साथ दिया।

गाँधी जी ने 1941 में ही नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी मान लिया था। विवाद की जड़ में विदेश मंत्री जयशंकर का यह कहना कि नेहरू-पटेल को कांग्रेस मंत्रीमंडल में शामिल करना नहीं चाहते थे। यह पूर्णतया निराधार है। पार्टीशन के अंतिम दौड़ में वायसरायमाउंटबेटन के नजदीक नेहरू थे। जबकि उनके सचिव बी पी मेनन के करीब पटेल थे। पार्टीशन के सभी दस्तावेज व राय की मुख्यता इन्हीं को जानकारी थी और इन दोनों ने ही आपसी सहयोग से निर्णय लिए। यह इसलिए पता चलता है कि 14-15 जून 1947 को आल इंडिया कांग्रेस कमिटी की मीटिंग में जब 3 जून को माउंटबेटनप्लान पास होने जा रहा था तो काफी काँग्रेस सदस्यों ने इसका विरोध किया जिसमे मुख्य रूप से सिंध प्रांत के छोटू राम गिडवानी ने विरोध किया और जिन्होंने मुस्लिम लीग के आगे काँग्रेस का आत्मसमर्पण माना। पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी पार्टिशन का विरोध किया। जय प्रकाश नारायण और लोहिया ने पार्टिशन को अप्पोज किया। मौलाना आज़ाद अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे रहे और दुख के मारे उन्होने एक शब्द भी नहीं बोला। आचार्य कृपलानी ने डिबेट में कोई हिस्सा नहीं लिया। इस मौके पर गांधी जी ने केवल दो पॉइंट रखे। सबसे पहले उन्होनेनेहरू से पूछा कि उन्होनेपार्टिशन के प्लान के बारे में क्यो नहीं बताया गया। नेहरू ने गांधी जी को बीच में ही रोकते हुये कहा कि आप नोआखाली में थे जो बहुत दूर था इसलिए हम आपको पार्टिशन की डीटेल नहीं बता सके। उसके बाद उन्होने पटेल की तरफ देखा और पटेल ने भी नेहरू का ही साथ दिया। गांधी ने दूसरा पॉइंट यह रखा कि विभाजन पर पटेल और नेहरू ने कमिटमेंट कर दिया तो काँग्रेस को इस विभाजन को मानना पड़ेगा। मीटिंग के दौरान राम मनोहर लोहिया ने यह ऑब्जर्व किया कि गांधी के दोनों शिष्य गांधी के प्रति उत्तेजनात्मक भाषा का प्रयोग किया। यहाँ तक कि वह गांधी से उग्रतापूर्वक पेश आए तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पटेल और नेहरू ने ही मुख्यता विभाजन में वार्ता की। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे। गांधी ने भी उनके इस व्यवहार को देखकर इसे अपने जीवन का महाब्लंडर बताया।

> इतिहास के पन्नो में भी नेहरू-पटेल-गाँधी के बीच दरार के कई किस्से मौजूद हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके बीच वैमनस्यता, कटुता व घृणा के भाव थे। उनके विचार समय समय पर आपस में टकराहट जरूर पैदा करते थे, सशक्त रूप से आपस में सहयोग भी करते थे।

प्रश्न उठता है कि आखिर इस विवाद से फ़ायदा किसको हुआ

लेखक फ्रैंकडिकोटर ने अपने किताब "कल्ट ऑफ पर्सनालिटी" में लिखा कि पर्सनालिटी को बढ़ावा देने के लिए स्वेक्षाचारी नेता एक बड़ा झूठ पैदा करता है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को झूठा बना देता है और जब सभी झूठ बोलने लगते है तो कोई भी यह नहीं जनता कि कौन सी बात झूठ है अतः किसी भी महापुरुष की गरिमा को गिराकर अपनी गरिमा बढ़ाई जा सकती है इसलिए आज देश में नयेनये मानक के तहत नये महापुरुषों की खोज जारी है। क्योकि किसी एक की छवि को गिराकर ही दूसरे को महान बताया जा सकता है। अब देश में नये महापुरुषों की खेप आने जा रही है।

दंगों के बाद सत्तानशीनों को गांधी की याद क्यों आती है ?

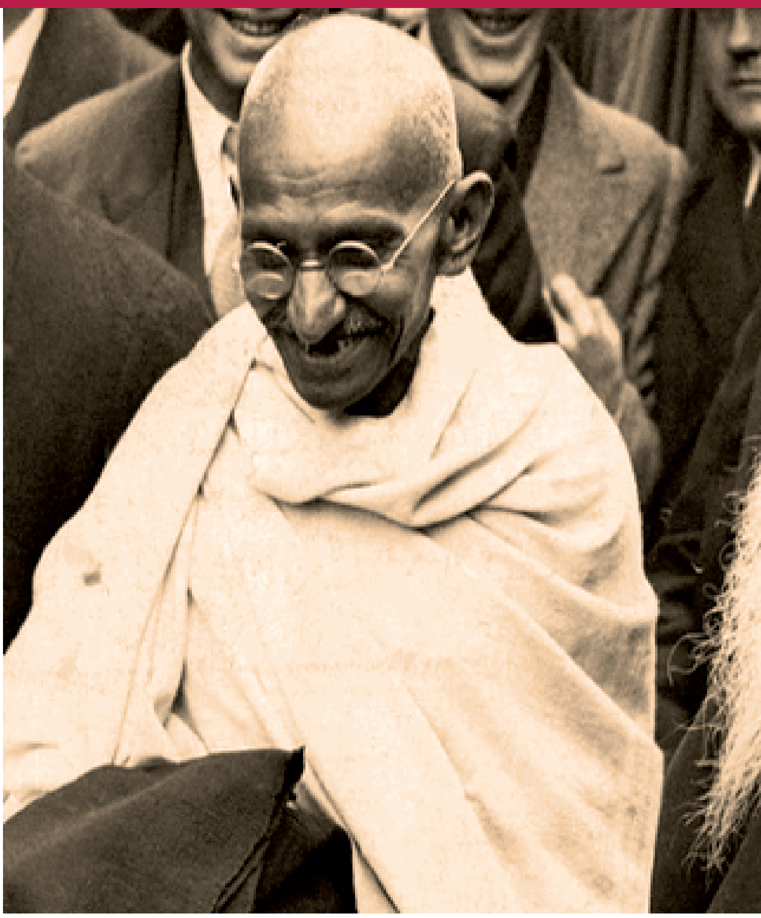

आज दिल्ली में चुनावी समीकरण में जीतने वाले बड़े भाषणबाज नेता, धमकाने वाले नेता, चैनलों पर उन्माद फ़ैलाने वाले नेता दिल्ली में रहते है। किसी भी नेता में यह नैतिक साहस नहीं है कि वह जनता का सामना कर सके। समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, कानूनविद व समाजशास्त्री सभी भयभीत हैं। लोकसभा व विधानसभा में पूर्ण बहुमत का दावा करने वाली सभी पार्टियां आज गाँधी की समाधी पर बैठे नज़र आ रहे है। सत्ता पक्ष अमन और शांति की अपील कर रहा है। आज देश गाँधी को याद कर रहा है। महात्मा गाँधी में इतना आत्मबल था कि विभाजन के दंगों के दौरान बंगाल में 13 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक अनशन करके हिंसा की हैवानियत को काबू में किया था और 30 जनवरी 1948 को अपनी शहादत देकर इस पूरे उपमहाद्वीप को शांत कर दिया था। इसी दिल्ली में जब विभाजन का दंगा हुआ तो निहत्थे व अप्रासंगिक गांधी जी को बंगाल से बुलाया गया और दंगा रोकने के लिए उनके नैतिक आत्मबल का उपयोग करने के लिए पूरी केंद्र सरकार बैचैन थी। वह जानती थी कि दंगों को बंदूकों के बल पर नहीं रोका जा सकता है। गृहमंत्री सरदार पटेल ने स्वयं सहादरा स्टेशन जाकर गाँधी जी को लेने पहुंचे और उन्हें सुरक्षा के लिहाज से बिरला हाउस में ठहराया गया जबकि वह दंगा प्रभावित क्षेत्र में ही रहना चाहते थे। दंगों के बारे में गाँधी जी कहते हैं कि "दंगों के कथित विजेता सचमुच विजयी हुए है, या कहीं अपने दुश्मन को गिराने की चाह और कोशिश में खुद में ही तो नहीं गिर गए हैं।"

किसी भी हालत में यह नुकसान का ही सौदा कहा जायेगा। जिसे हम बर्बाद करते हैं, दरअसल वह तो हमारी ही सम्पत्ति है। उसका ज्यादातर हिस्सा, चाहे वह आदमियों की सूरत में हो या चीज़ों की यह सब यही पैदा होता है इस पर लोगों का केवल कब्ज़ा होता है। हमे ही इस सम्पत्ति की बर्बादी की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उनका बोझ बेगुनाहों और गरीब जनता पर पड़ता है। सच तो यह है कि हमारे नेताओं ने अपने दिल में हिंसा को छिपाये रखकर केवल ज़बान से अहिंसा का उपदेश देते हैं। परन्तु सीधी-साधी जनता इन दिलों में छिपे भावों का मतलब नहीं समझ पाती। पाखंडियों ने अहिंसा की तो प्रशंसा की है लेकिन उनका ज्यादा जोर हिंसा पर ही रहा है। देश की इस महजूदा स्थित में अहिंसा का प्रयोग किस तरह किया जाए, लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा।

गाँधी जी भी उसी प्रकार असफल हुए जिस प्रकार मनुष्य को हिंसा से हटाने में बुद्ध तथा ईसा मसीह असफल रहे परन्तु लोग इन्हें सदा ऐसे व्यक्ति की तरह याद करेंगे जिसने अपने जीवन की कुर्बानी देकर लोगों मनुष्यता पाठ पढ़ाया।

क्या जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू सरकार का रिकॉर्ड तोड़ेगी मोदी सरकार ?

इंदिरा सरकार के समय फारुखअब्दुल्लाह के बहनोई जी० एम० शाह के नेतृत्व में बनी सरकार के शुरुवाती90 दिनों में 72 दिन कर्फ्यू लगा रहा। जनता ने शाह की सरकार को कर्फ्यू सरकार की संज्ञा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त को धारा 370 हटाया है तब से लेकर अभी तक किसी न किसी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। सवाल यह उठ रहा है कि पुराने कर्फ्यू सरकार का रिकॉर्ड मोदी सरकार में टूट जायेगा। कांग्रेस आज जो भी लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर भाजपा सरकार का विरोध कर रही है यह ऐतिहासिक सच है कि कांग्रेस ने भी सत्ता के मद में लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन किया है।

इंदिरा गाँधी ने जम्मू कश्मीर में शाह अब्दुल्लाह के निधन के बाद फारुखअब्दुल्लाह को मुख्यमंत्री बनवाया लेकिन जब फारुख ने (जम्मू एंड कश्मीर ग्रांटऑफ़परमिटफॉररिसेटेलमेंट) पुनर्वास बिल को लेकर मतभेद पैदा हुआ तो इंदिरा गाँधी ने फारुख को हटाने का मन बना लिया। 13अक्टूबर1983 दौरान जब श्रीनगर में भारत वेस्टइंडीज़ एक दिवसीय क्रिकेट मैच के दौरान खुलेआम देशद्रोही तत्वों ने पाकिस्तानी झंडा फहराया तो इंदिरा गाँधी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बी के नेहरू को फारुख की सरकार बर्खास्त करने की रिपोर्ट देने के लिए दवाब बनाया लेकिन बी के नेहरू ने इंदिरा गाँधी की बात नहीं मानी और रातोरात उनका तबादला किया गया और जगमोहन को नए राज्यपाल की कमान दी गयी। जगमोहन ने इंदिरा गाँधी के इशारे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 13 विधायकों से समर्थन वापसी का पत्र लेकर जी एम शाह को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। जबकि फारुखअब्दुल्लाह सविधान की धारा 92 के तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कराना चाहते थे लेकिन इंदिरा गाँधी राजी नहीं हुई। जी एम शाह के नेतृत्व में बनी सरकार के शुरुवाती 90 दिनों में जनता की आक्रोश 72 दिन कर्फ्यू लगा रहा है और जनता कर्फ्यू सरकार कहने लगी।

13अक्टूबर1983 दौरान जब श्रीनगर में भारत वेस्टइंडीज़ एक दिवसीय क्रिकेट मैच के दौरान खुलेआम देशद्रोही तत्वों ने पाकिस्तानी झंडा फहराया तो इंदिरा गाँधी ने जम्मू कश्मीर के राजयपालबी के नेहरू को फारुख की सरकार बर्खास्त करने की रिपोर्ट देने के लिए दवाब बनाया लेकिन बी के नेहरू ने इंदिरा गाँधी की बात नहीं मानी और रातोरात उनका तबादला किया गया और जगमोहन को नए राज्यपाल की कमान दी गयी।

कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर में समय समय पर मतभेदों को लेकर सरकार गिराने और सरकार बनवाने का कार्य किया

है। शाह ने मुख्यमंत्री बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के 13 विद्रोही विधायकों को कैबिनेट मंत्री बना दिया। ढाई साल तक चली शाह की सरकार भ्रष्टतम सरकार में गिनी जाती है। जम्मू कश्मीर को लेकर जो आरोप लग रहे है कि दो परिवारों ने सत्ता की भागीदारी की और मनमाने तरीके से लुटा। ऐतिहासित तथ्य यह है कि तमाम उतार चढ़ावों के बीच शेख अब्दुल्लाह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने अन्तिम दिनों में पुत्र मोह में फारुख अब्दुल्लाह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उत्तराधिकारी का चयन लोकतांत्रिक ढंग से न कर एक पारिवारिक सत्ता हस्तांतरण का मामला बन गया। जीवन भर शेख के हर संघर्ष में साथ रहे अफजल बेग को 1978 में गद्दारी का आरोप लगा कर पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी में शेख के दामाद जी0एम0 शाह और बेटे फारुख का प्रभुत्व बढ़ता गया। जी० एम0 शाह खुद को शेख साहब का उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन शेख साहब ने बेटे के पक्ष में फैसला लिया और 21 अगस्त 1981 को इकबाल पार्क की सार्वजनिक सभा में उन्होंने फारुख को "काटों का ताज पहनाने की घोषणा कर दी और मेडिकल की शिक्षा हासिल करके लौटे फारुख को अपने मंत्रीमंडल में स्वास्थ मंत्री के रूप में शामिल किया।" 8 सितम्बर 1982 को शेख अब्दुल्लाह की मृत्यु हो गयी। एम0जे0 अकबर कहते है कि "शेख अब्दुल्लाह तमाम उतार चढ़ाव के बीच वह एक हिन्दुस्तानी की तरह जीये और हिन्दुस्तानी की तरह ही मरे।" इंदिरा गाँधी ने शेख की मृत्यु की खबर मिलते ही सबसे पहले फारुख के मुख्यमंत्री पद को सुनिश्चित किया। कश्मीरियों तक यह खबर पहुंचने से पहले ही कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गयी। जिसमे जी0एम0 शाह ने फारुख के नाम का प्रस्ताव किया और डीडी ठाकुर ने सर्मथन किया। रात के 10 बजे फारुख ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फारुख को सबसे पहले जिस समस्या से रूबरू होना पड़ा वह थी पुनर्वास बिल (जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ़ परमिट फॉर रिसेटेलमेंट) इसे लोगों ने उपद्रवी कानून कहा और इस कानून से सबसे बड़ा खतरा था कि भारत के विरोधी तत्व कश्मीर में स्थापित हो जायेंगे।

यह बिल विधानसभा में पास न हो सका। इसी पुनर्वास बिल के मुद्दे पर इंदिरा गाँधी व फारूख ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। परिणाम स्वरुप चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसी स्थिति पैदा हुई। जहाँ जम्मू में भाजपा के परम्परागत सीटों पर कांग्रेस ने कब्ज़ा किया वहां उसे 26सीटों और 30.1प्रतिशत वोट हासिल किये लेकिन घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 46सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। भीम सिंह की पैंथर पार्टी और अब्दुल गनी लोन की पीपल कॉन्फ्रेंस को 1-1 सीट मिली। भाजपा को कोई सीट न मिली। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच वैमनस्य बढ़ता गया। फारुख ने श्रीनगर की जामा मस्जिद से घोषणा की कि मैं कांग्रेस से देश की हर गली, हर नुक्कड़ पर लडूंगा और वह देश के प्रमुख विपक्षी नेताओ के साथ शामिल हो गए। यह इंदिरा गाँधी के लिए एक चुनौती जैसा था। इसी बीच 13अक्टूबर1983 के दौरान श्रीनगर में भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच के दौरान उपद्रवी तत्वों ने मैच में बाधा पहुंचाने की कोशिश की और खुलेआमपाकिस्तानी झंडे लहराए गए।

इंदिरा गाँधी को अवसर मिल गया उन्होंने फारुख की सरकार को बर्खास्त करने के लिए बी० के० नेहरू को कहा लेकिन उन्होंने इंदिरा गाँधी की बात नहीं मानी जिससे नाराज होकर इंदिरा गाँधी ने उनका तबादला करते हुए अप्रैल 1984 में जगमोहन को राज्यपाल बना के भेजा गया और कांग्रेस की शह पर जी0एम0 शाह के नेतृत्व में 1 जुलाई को नेशनल कांग्रेस के 13 विधायकों ने राज्यपाल से संपर्क किया और समर्थन वापस लेने की बात कही। जगमोहन ने उनका पूरा सहयोग किया और फारुख की जल्दबाज़ी तथा भावुकता ने उनका काम और आसान कर दिया।

फारुख अब्दुल्लाह ने सविधान की धारा 92 के तहत

राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इंदिरा इस पर राजी नहीं थी और अंतत उसी शाम जी0 एम0 शाह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शाह ने सभी 13 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बना दिया। 31 जुलाई को शाह ने अपना बहुमत साबित कर दिया और कश्मीर के इतिहास में शायद सबसे भ्रष्ट सरकार का दौड़ अगले ढाई साल सत्ता में रहा। शाह को कश्मीरी जनता का तीखा विरोध झेलना पड़ा। सत्ता के पहले 90 दिनों में से 72 दिनों का कर्फ्यू लगा रहा और जनता ने इसे कर्फ्यू सरकार का नाम दिया। (इसी बीच 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खोलने के निर्णय के बाद पहली बार अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों के घर और मंदिर जलाने की घटनाएं हुई। अनंतनाग मुफ्ती मोहम्मदसईद का क्षेत्र था और उन पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया इसके पीछे पूर्णतया मुफ्ती साहब का हाथ था।) 31 अक्टूबर1984 को इंदिरा गाँधी की हत्या हो गयी जनवरी 1985 में राजीव गाँधी और फारुखअब्दुल्लाह की मुलाकात हुई। यहाँ मुफ्ती मोहम्मद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे लेकिन राजीव गाँधी ने एक बार फारुख से समझौता करना उचित समझा। 7 मार्च 1986 को जी0 एम0 शाह की सरकार बर्खास्त कर दी गयी और आज़ादी के बाद पहली बार "कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा" जगमोहन अगले 6 महीने कश्मीर के प्रशासक रहे। राजीव गाँधी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का प्रस्ताव रखा और इस बार फिर फारुखअंतत इसके लिए राजी हो गए। बलराज पूरी लिखते है कि "फारुख की देश भक्ति पर से सन्देश जल्दी दूर हो गया जब उन्होंने विपक्ष से सम्बन्ध तोड़ कर कांग्रेस से सम्बन्ध सुधार लिए और कांग्रेस ने उन्हें देशभक्ति का प्रमाण पत्र जारी कर मुख्यमंत्री बनाने में हमेशा सहयोग किया" फारुख अब्दुल्लाह भी समय समय पर रंग बदलते रहे और अटल बिहारी सरकार में भी फारुखअब्दुल्लाह शामिल हुए। बदली परिस्थियों में फारुख कांग्रेस के साथ तो पीडीपी की महबूबा मुफ़्ती भाजपा के साथ खड़ी रही। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद महबूबा ने 3 साल तक भाजपा के साथ मिल कर सरकार चलायी। भाजपा ने अपने एजेंडे को लागू करने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले महबूबा से रिश्ता तोड़ा और 2019 में अपार बहुमत मिलने के बाद धारा 370 और 35A को हटा दिया। इस मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ फारुख और महबूबा दोनों है। कांग्रेस 370 का सीधा विरोध तो नहीं कर रही लेकिन कांग्रेस इसे लागू करने के तरीके पर सवाल उठाती रही।

5 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर तक 62 दिन पूरे हो गए और जम्मू कश्मीर में पूरी तरह कर्फ्यू नहीं हटा है। स्थिति सामान्य होने की तरफ बढ़ रही है। फारुखअब्दुल्लाह और मुफ्ती से पार्टी के नेताओ को मिलने की इज़ाज़त दे गयी लेकिन सवाल आज भी यही उठ रहा है कि पूरे कश्मीर से कर्फ्यू कब हटेगा? क्या 72 दिनों के पुराने रिकॉर्ड मोदी सरकार में टूट तो नहीं जायेगा।

8 सितम्बर 1982 को शेख अब्दुल्लाह की मृत्यु हो गयी। एम0जे0 अकबर कहते है कि "शेख अब्दुल्लाह तमाम उतार चढ़ाव के बीच वह एक हिन्दुस्तानी की तरह जीये और हिन्दुस्तानी की तरह ही मरे।" इंदिरा गाँधी ने शेख की मृत्यु की खबर मिलते ही सबसे पहले फारुख के मुख्यमंत्री पद को सुनिश्चित किया।

आंकड़ों के आईने में

भारत जोड़ों यात्रा

ALL INDIA - TENTATIVE YATRA SCHEDULE

STATE	ENTRY DATE	No. of DAYS	KEY PLACES
Karnataka	30th - Sept	21	Mysore, Bellary, Raichur
Andhra Pradesh	20th - Oct	02	Alur
Telangana	23rd - Oct	12	Vikarabad
Maharashtra	05th - Nov	14	Nanded, Jalgaon, Jamod
Madhya Pradesh	20th - Nov	16	Indore, Ujjain
Rajasthan	06th - Dec	18	Alwar, Kota, Dausa
Haryana	24th & 30th - Dec	12	Ambala
**Note: Yatra enters Haryana twice - first on 24th Dec north Alwar, and next after Delhi*			
Uttar Pradesh	24th - Dec	05	Bulandhshahar
Delhi	28th - Dec	02	Rajghat
Punjab	10th - Jan	11	Pathankot
Route after 10th Jan will be released in due course.			

द डाटा स्ट्रीट
हिन्दी मासिक पत्रिका

– अमन सिन्हा

राहुल गाँधी की भारत जोड़ों यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही नहींराहुल गाँधी और कांग्रेस के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। 150 दिनों तककन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली 3570 किलोमीटर की यात्रा राहुल गाँधीका भी राजनीति में फुलटाइमर बनने की अग्निपरीक्षा साबित होगी। देश में जो हालात है निश्चित रूप से भारत जोड़ों यात्रा कीबहुत बड़ी आवश्यकता थी। समय काल परिस्थितियों के अनुसार जो राजनीतिक हालातदेश में बने है उसमें राहुल गाँधी की भारत जोड़ों यात्रा भाजपा सरकार केसामने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर सकती है। आजादी के 75 वर्ष बाद देश में जिसतरह से सामाजिक एवं धार्मिक आधार पर बटवारा हो रहा है। जातियों के बीच गहरीखाई बढ़ती जा रही है। भाजपा हो या गैर भाजपा शासित राज्य पूरे देश मेंसामाजिक समरसता टूटी है। भाईचारा कम हुआ है। गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ीहै। ऐसे में राहुल गाँधी के नेतृत्व में 100 से अधिक सामाजिक संगठनों कीभारत जोड़ों यात्रा देश में नया राजनीतिक जन जागरण बना सकती है जो 2024 मेंभाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।

समय की पुकार भी और मोदी सरकार के खिलाफ उपजे जन भावना को जोड़ने का बेहतर प्रयास भी कहा जा सकता है। निश्चित रूप से भारत जोड़ोंयात्रा के पहले राहुल गाँधी ने दिल्ली के राम लीला मैदान में मोदी सरकार केखिलाफ जिन मुद्दों को उठाया है वह सभी जनता से जुड़े हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी के साथ समाज में हो रहा बिखराव देश के सामने गंभीर समस्या है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद कह चुके है कि सरकार बनाना आसान है लेकिनदेश बनाना बहुत मुश्किल है राहुल गाँधी भी कहते है चुनाव जीता जा सकता है लेकिन देश चला पाना चुनौती पूर्ण होता है।

विपक्ष कमजोर है देश मेंसमस्याओं का अंबार है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ों यात्रा जनता कोजोड़ने में कितना सफल होती हैं यह उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगर राहुलगांधी भारत जोड़ों यात्रा से जनता से सीधा संवाद करने में सफल रहे तोकाँग्रेस के अंदर गांधी परिवार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ दब जाएगी औरराष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गांधी परिवार का वर्चस्व बने रहने पर भाजपाको कोई विरोध काम नहीं करेगा। भारत जोड़ों यात्रा मोदी और राहुल दोनोंके सामने चुनौती है। समय तय करेगा कि भारत जोड़ों यात्रा से किसे बड़ीचुनौती 2024 में मिलेगी।

> महंगाई, बेरोजगारी के साथ समाज में हो रहा बिखराव देश के सामने गंभीर समस्या है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद कह चुके है कि सरकार बनाना आसान है लेकिनदेश बनाना बहुत मुश्किल है राहुल गाँधी भी कहते है चुनाव जीता जा सकता है लेकिन देश चला पाना चुनौती पूर्ण होता है।

वैसे यह पहली यात्रा नहींहै। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद देश में बहुत यात्रायें हुई हैं। गाँधीका **दांडी मार्च** आज़ादी दिलाने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब न कोईमहात्मा गाँधी है और न वैसा जन समर्थन मिल सकता है। पूर्व प्रधानमंत्रीचंद्रशेखर ने भी 1983 में 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक 4200 किलोमीटर कीयात्रा **भारत जोड़ों** के नाम पर की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधीके सामने भारत जोड़ों यात्रा ने एक ऐसा जन जागरण कांग्रेस के खिलाफ देश मेंबना दिया था। राजनीतिक विशेषज्ञ यह मानते है कि जो हालात चंद्रशेखर की भारतयात्रा, मेनका गाँधी द्वारा गठित संजय विचार मंच और इन्दिरा गाँधी विरोधी बड़े-बड़े नेताओं ने मिलकर बनाया था। अगर 31 अक्टूबर1984 को श्रीमती इन्दिरागाँधी की हत्या नहीं हो गयी होती तो देश की सियासत का रूख अलग होता। **इन्दिरा विरोधी जनजागरण** उनकी हत्या के बाद सहानुभूति में बदल गया औरकांग्रेस अपने इतिहास में 415 सांसद जीत कर राजीव गाँधी के नेतृत्व में एकरिकॉर्ड बनाया।

आईये ! देश में यात्राओं का इतिहास पर नजर डालते हैं-

दांडी यात्रा (1930)

भारत के इतिहास में स्वाधीनताआंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांड़ी यात्रा को सबसेचर्चित माना जाता है।महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार द्वारा नमक पर टैक्सलगाए जाने के विरेध में 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद साबरमती आश्रमसे पैदल यात्रा शुरू की।दांड़ी यात्रा को देशभर से मिलते समर्थन को देखतेहुए 6 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों ने नमक से टैक्स का कानून वापस ले लिया।

1982: एनटीरामाराव की चैतन्य रथम यात्रा

आंध्र प्रदेश में वर्ष 1982 में एनटीरामाराव ने चैतन्य रथम यात्रानिकाली। 75 हजार किलोमीटर लंबी इस यात्रा ने प्रदेश के चार चक्कर लगाए जोकिगिनीज बुक आफवल्र्ड रिकार्ड में है। 29 मार्च 1982 को नंदमूरी तारकरामाराव ने तेलुगु सम्मान के मुद्दे पर तेलुगुदेशम पार्टी का गठन किया

औरदेश की पहली राजनीतिक रथयात्रा शुरू की। एक शेवरलेवैन में बदलाव करके रथबनवाया गया। एनटीआर एक दिन में 100-100 जगहों तक रुकते। वह इतना लोकप्रियथे कि जनता इंतजार करती थी, महिलाएं उनकी आरती उतारती थीं। यात्रा के बादविधानसभा चुनाव में तेलुगुदेशम पार्टी को 294 में से 199 सीटें मिलीं औरएनटीआर आंध्र प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने।

चंद्रशेखर की 'भारत यात्रा' (1983)

चंद्रशेखरने 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक कन्याकुमारी से राजघाट (महात्मा गांधीकी समाधि) तक भारत यात्रा निकाली थी. यह पदयात्रा 4260 किलोमीटर की हुई थी.चंद्रशेखर की इस पदयात्रा का मकसद लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं कोसमझना था. उन्होंने

1990: आडवाणी की राम रथ यात्रा

वर्ष 1990 में भाजपा ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन को तेज करते हुए पूरे देश में भ्रमण करते हुए अयोध्या तक रथयात्रा की घोषणा की। इस यात्रा के सारथी बने लालकृष्णआडवाणी। रथयात्रा 25 सितंबर को गुजरात में तीर्थस्थल सोमनाथ से शुरू हुई और सैकड़ों शहरों व गांवों से होकर गुजरते हुए बिहार पहुंची। तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद ने समस्तीपुर में रथयात्रा रोककर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इस रथयात्रा ने भाजपा को राष्ट्रीय

केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में 15 भारत यात्रा केंद्रों की स्थापना की ताकि वे देश के पिछड़े इलाकों में लोगों को शिक्षित करने और जमीनी स्तर पर काम कर सकें.

चंद्रशेखर की भारत यात्रा की शुरुआत और मकसद बिखरती जनता पार्टी को एकसूत्र में बांधना था, साथ ही उनमें जोश कासंचार करना था. हालांकि इस बीच इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर हार जाते हैं. लेकिन इस यात्रा के जरिए उन्होंने खुद को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा चेहरा बना लिया और दक्षिण से लेकर उत्तर तक के नेताओं से भी अच्छी-खासी दोस्ती हो गई. बाद में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री भी बने.

पार्टी के रूप में एक नई पहचान और जनता के बीच लोकप्रियता दी। कहा जाता हैकि यहीं से भाजपा की राजनीतिक यात्रा ने करवट ली और एक नए दौर में

प्रवेशकिया। रथयात्रा के बीच राममंदिर आंदोलन में भारी संख्या में कार सेवकअयोध्या पहुंचे। वर्ष 1991 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को 120 सीटें मिलीं जो पिछले चुनाव से सीधे 35 अधिक थीं।

2004: वाईएस राज शेखर रेड्डी की पैदल यात्रा

कांग्रेस के कद्दावर नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी ने वर्ष 2004 में आंध्रप्रदेश के चेवेल्ला शहर से 1,500 किमी पैदल यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा 11 जिलों से होकर गुजरी। जनता राजशेखर को मसीहा मानती थी, लोग उनसे मिलने उमड़े । विधानसभा चुनाव में 294 में से 185 सीटों पर कांग्रेस की जीत केसाथ 10 वर्ष से जारी टीडीपी का शासन खत्म हुआ और वाईएस राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बने।

2017: जगनमोहन रेड्डी की प्रजा संकल्प यात्रा

आंध्र प्रदेश में ही वर्ष 2017 में निकाली गई इस यात्रा ने युवा जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। वर्ष 2009 में वाईएस राजशेखर रेड्डी की हेलीकाप्टर दुर्घटना में मौत के बाद कांग्रेस ने उनकेबेटे जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने से इन्कार कर दिया था। इसके बादजगमोहन ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का गठन किया। पिता की आंध्र प्रदेश यात्रा की तरह पद यात्रा

निकाली जो उनके राजनीतिक करियर की खेवनहार बनी। छहनवंबर 2017 में उन्होंने कडप्पा जिले से पदयात्रा शुरू की। जो 430 दिन में 13 जिलों के 125 विधानसभा क्षेत्रों से 3,648 किमी की दूरी तय करते हुए श्री काकुलम तक पहुंची। रथ यात्रा के बाद वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस को 175 में से 152 सीटों पर विजय मिली और जगन मोहन सीएम बने।

नर्मदा परिक्रमा पद यात्रा 30 सितंबर 2018

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा पद यात्रा की नरसिंहपुर जिले से शुरुआत की। यह यात्रा 192 दिनों तक चली, जिसने 3,300 किलोमीटर की दूरी तय की। दिग्विजय सिंह के साथ उनकी पत्नी भी इस यात्रा में शामिल थीं। नर्मदा परिक्रमा पद यात्रा पवित्र नर्मदा नदी के दोनों किनारे तक हुई थी। इस यात्रा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीवनदान दे दिया और पार्टी को 114 सीटों पर जीत मिली. कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

अब कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से काफी उम्मीदें हैं. अब देखना यह होगा कि देश की जनता कांग्रेस के द्वारा उठाए गए मुद्दों को कितना सुनेगी और एक बार फिर से पार्टी पर भरोसा करेगी। लेकिन इसके साथ ही सवाल कांग्रेस की इस यात्रा में यूपी-बिहार को तवज्जो न मिलने पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

भारत जोड़ो यात्रा 2022

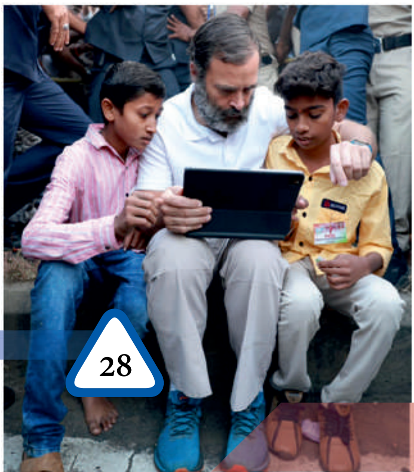

2014 से अब तक कितना बदला संविधान

– सुजीत श्रीवास्तव

"संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है, यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों. यह कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उसके दल कैसाआचरण करेंगे. अपना मक़सद हासिल करने के लिए वे संवैधानिक तरीके अपनाएंगे या क्रांतिकारी तरीके? यदि वे क्रांतिकारी तरीके अपनाते हैं तो संविधान चाहे जितना अच्छा हो, यह बात कहने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं कि वहअसफल ही रहेगा."

संविधान बनाने के बाद भीमराव आंबेडकर ने ये भाषण नवंबर 1949 को नई दिल्ली में दिया था.आंबेडकर के इस भाषण के कुछ ऐसे ही अंश अक्सर तब सुने जाते हैं जब 'संविधान केअनुरूप काम नहीं करने' के आरोप सत्तारूढ़ दलों पर लगाए जाते हैं. **संविधान की प्रस्तावना में बदलाव हो, जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली हो, दल-बदल क़ानून हो, जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म करना हो या फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात.**

ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर अक्सर पक्ष और विपक्ष में तीखी जुबानी जंगलड़ी जाती रही है और हर मर्तबा हवाला दिया जाता है संविधान का.

संविधान जिसे 73 साल पहले 26 नवंबर 1949 के दिन अपनाया गया और तब से हरसाल ये तारीख़ संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है. यानी आज संविधान कोअपनाए जाने की 73वीं वर्षगांठ है.

द डाटा स्ट्रीट
हिन्दी मासिक पत्रिका

संशोधित संविधान

(2022 तक)
448 अनुच्छेद,
25 भागों में विभाजित, 12 अनुसूचियां

मूल संविधान

(16 नवम्बर 1949)
395 अनुच्छेद,
22 भागों में विभाजित, 8 अनुसूचियां

भारतका संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है. इसके अनुच्छेद 368 केआधार पर संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है.

संविधान में पहला संशोधन 1951 में अस्थायी संसद ने पारित किया था. उस समय राज्यसभा नहीं थी. पहले संशोधन के तहत 'राज्यों'को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की प्रगति के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार दिया गया था. यूँ तो अब तक संविधान में 105 संशोधन किएजा चुके हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन कियागया है.

लघु संविधान

ये संशोधन इंदिरा गांधी के शासन के आपातकाल के दौरान हुआ था. ये 42वां संविधान संशोधन था और अब

संविधान संशोधन विधेयक तीन प्रकार के है-

1. ऐसे विधेयक जो संसद (लोकसभा और राज्य सभा) से साधारण बहुमत से पास किए जाते हैं.
2. ऐसे विधेयक जो संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के मुताबिक विशेष (दो-तिहाई) बहुमत से पारित किए जाते हैं.
3. ऐसे विधेयक जो संसद से विशेष बहुमत से पारित हैं और जिनके लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन जरूरी है.

तक का सबसे व्यापक और विवादास्पद. उस वक्त ऐसा लगाथा कि इस संशोधन के द्वारा सरकार कुछ भी बदल सकती है.शायदयही वजह है कि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है. इसमें संविधान की प्रस्तावना में तीन नए शब्द- समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए.

1976 में किए गए 42वें संशोधन में अहम बात ये थी कि किसी भी आधार पर संसद के फ़ैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी.

साथ ही सांसदों एवं विधायकों की सदस्यता को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी. किसी विवाद की स्थिति में उनकी सदस्यता पर फ़ैसला लेने का अधिकार सिर्फ़ राष्ट्रपति को दे दिया गया और संसद का कार्यकाल भी पांच साल से बढ़ाकर छह साल कर दिया गया.

इस संविधान संशोधन को लेकर सड़क से लेकर संसद तक जमकर बवाल और सियासत हुई. 1977 में सत्ता में आने के बाद तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने इस संशोधनके कई प्रावधानों को 44वें संविधान संशोधन के ज़रिए रद्द कर दिया. इनमें सांसदों को मिले असीमित अधिकारों को भी नहीं बख्शा गया, हालाँकि संविधान की प्रस्तावना में हुए बदलाव से कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई.

अबतक हुए संविधान संशोधनों में से कई को अदालत में चुनौती दी गई है, लेकिन देश के उच्चतम न्यायालय ने केवल 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है. यह संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एनजेएसी क़ानून) के गठन के संबंध में था.

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की 22 साल पुरानी कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले एनजेएसी क़ानून, 2014 को निरस्त कर दिया था.

पांच जजों की संविधान पीठ ने चार-एक के बहुमत से दिए फैसले में एनजेएसी कानूनऔर संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 दोनों को असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित किया था.

लगातार 10 साल तक चली मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को हटाकर एनडीएगठबंधन ने साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता संभाली. इसके बाद से सरकार के कई फ़ैसलों और इसके द्वारा लाए गए कई नई अध्यादेशों और क़ानूनों को लेकर ख़ासा विवाद रहा है. इस दौरान कुल मिलाकर संविधान में छह संशोधन किए गए.

2014-22 में हुए संविधान संशोधन

99वां संशोधन	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (2015)
100वां संशोधन	भारत-बांग्लादेश के बीच भू-सीमा संधि (2015)
101वां संशोधन	वस्तु एवं सेवाकर यानी जीएसटी अधिनियम (2016)
102वां संशोधन	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा (2018)
103वां संशोधन	EWS को शिक्षण संस्थाओं, नौकरियों में 10% आरक्षण (2019)
104वां संशोधन	लोकसभा, विधानसभाओं में SC,ST आरक्षण 10 साल बढ़ा (2019)
104वां संशोधन	सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान (2021)

जानें मोदी सरकार के आठ साल

के शासन के दौरान कितना बदला संविधान

99वां संविधान संशोधन

नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक अहम फ़ैसला लिया, वो था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने की दिशा में आगे बढ़ना. इस आयोग के ज़रिये केंद्र सरकार न्यायाधीशों का चयन ख़ुद करने में सक्षम हो जाती. क़ानून के तहत प्रावधान ये था कि जजों की नियुक्ति करने वाले इस आयोग की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश को करनी थी.

इसकेअलावा सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, क़ानून मंत्री और दोजानी-मानी हस्तियां भी इस आयोग का हिस्सा थीं. इन दो हस्तियों का चयन तीनसदस्यीय समिति को करना था जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल थे. इसमें दिलचस्प बात ये थी कि इस क़ानून की एक धारा के तहत अगर आयोग के दो सदस्य किसी नियुक्ति पर सहमत नहीं हुए तो आयोग उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफ़ारिश नहीं करेगा.

इस संविधान संशोधन पर 29 राज्यों में से गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात और तेलंगाना समेत 16 राज्यों की विधानसभाओं ने अपनी मुहर लगाई. तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के इस विधेयक को मंज़ूरी देने के साथ ही इस संविधान संशोधन ने क़ानून की शक्ल ले ली. लेकिन इस क़ानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई.

याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ नेचार-एक के बहुमत से इस संविधान संशोधन क़ानून को रद्द कर दिया. अदालत नेकहा कि जजों की नियुक्ति पुराने तरीक़े- कॉलिजियम सिस्टम से ही होगी.

105
बार भारत के संविधान में किया गया बदलाव, जून 1951 में पहला संशोधन

7
बार नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल (2014-22) में संविधान में हुआ संशोधन

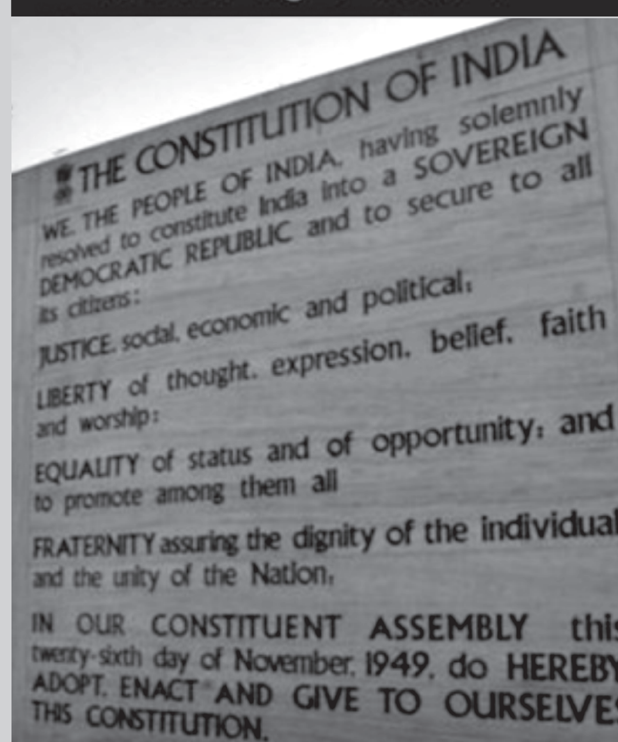

100वां संविधान संशोधन

भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू-सीमा संधि के लिए संविधान में 100वां संशोधन किया गया. 1 अगस्त 2015 को लागू इस क़ानून से न केवल 41 सालों से पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ चल आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़े, बल्कि अधिनियम बनने के बाद दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भू-भागों का आदान-प्रदान किया. समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई.

दरअसल, भारत में 111 जबकि बांग्लादेश में ऐसे 51 इन्क्लेव थे जहां रहने वाले लोगों को किसी भी देश के नागरिक होने का अधिकार प्राप्त नहीं था. भारत में यह क्षेत्र पूर्वोत्तर के असम, त्रिपुरा, मेघालय और पूर्वी बंगाल केहिस्सों में स्थित थे. यह इन्क्लेव किसी द्वीप की तरह ही कुछ ऐसे बसे थे किएक देश के नागरिकों की आबादी के हिस्से चारों ओर से दूसरे देश की ज़मीन औरउसके निवासियों से घिरे हुए थे.

सदियों पहले राजाओं के जमाने में हुए ज़मीन के बंटवारे के कारण ऐसी स्थिति बनी थीऔर वही व्यवस्था 1947 में ब्रिटिश शासन के ख़त्म होने और 1971 मेंबांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने के दौरान भी बरकरार रही. संविधान के संसोधन के बाद दोनों देशों के लिए अपने इन्क्लेवों की अदला-बदली करने का रास्ता खुल गया.

101वां संविधान संशोधन

देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में 101वां संशोधन किया गया. मकसद था राज्यों के बीच वित्तीय बाधाओं को दूर करके एक समान बाज़ार को बांध कर रखना. तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मंज़ूरी और राज्यों से सहमति मिलने के बाद एक जुलाई 2017 से यह लागू हो गया. जीएसटी राष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं के साथ-साथ वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर (मूल्य वर्धित कर) है.

जीएसटीएक ऐसी व्यवस्था बनी जिसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टैक्स) की जगह ली. दरअसल, जीएसटी विधेयक को क़ानून बनाने के लिए एक दशक से बात हो रही थी लेकिन राजनीतिक रस्साकशी के कारण ये अधर में लटक गया था. ड्राफ़्ट बिल से लेकर संसद में पास कराए जाने तक भारत को दस साल लगे.

'एक देश-एक कर' कहे जाने वाली इस सेवा को मोदी सरकार ने आज़ादी के सत्तर सालबाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया. यही नहीं जीएसटी लागू करने से कुछघंटे पहले मोदी सरकार ने 30 जून की आधी रात को सेंट्रल हॉल में एक विशेष सत्र बुलाया.

कहा गया कि 14 अगस्त 1947 को संसद के केंद्रीय कक्ष में आज़ाद भारत का जन्म हुआ था, इसी तर्ज़ पर मोदी सरकार ने जीएसटी लॉन्चिंग के लिए आधी रात को कार्यक्रम रखा, हालाँकि कांग्रेस समेत ज़्यादातर विपक्षी दलों ने विशेष सत्र का बहिष्कार किया.

102वां संविधान संशोधन

2018 में संसद ने संविधान में 102वां संशोधन पारित किया था जिसमें संविधान मेंतीन नए अनुच्छेद शामिल किए गए थे. नए अनुच्छेद 338-बी के ज़रिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया. इसी तरह एक और नया अनुच्छेद 342ए जोड़ा गया जो अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची से संबंधित है.

तीसरा नया अनुच्छेद 366(26सी) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करता है. इस संशोधन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला.

संवैधानिक दर्जा मिलने की वजह से संविधान में अनुच्छेद 342 एक जोड़कर आयोग को सिविल न्यायालय के बराबर अधिकार मिले. इससे आयोग को पिछड़े वर्गों की शिकायतों का निवारण करने का अधिकार मिला.

दरअसल, 1993 में वैधानिक संस्था के तौर पर स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां बेहद सीमित थीं. वह सिर्फ़ किसी जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में जोड़ने या हटाने की सिफ़ारिश ही कर सकता था. ओबीसी वर्ग की शिकायतें सुनने और उनके हितों की रक्षा का अधिकार अभी तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास था. संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद आयोग को ओबीसी के अधिकारों की रक्षा के लिए शक्तियां मिलीं.

103वां संविधान संशोधन

9 जनवरी, 2019 को संसद द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पारितकिया गया. यह अधिनियम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियोंको 10 फ़ीसदी आरक्षण का प्रावधान करता है. क़ानूनन आरक्षण की सीमा 50 फ़ीसदी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अभी तक देशभर में एससी, एसटी ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता था तो 50 फ़ीसदी की सीमा के भीतर ही मिलता था. लेकिन सामान्य वर्ग का 10 फ़ीसदी कोटा इस 50 फ़ीसदी की सीमा से बाहर है.

इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. 40 से अधिक याचिकाएं दाखिल होगई और दलील दी गई कि ये 10 फ़ीसदी आरक्षण संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि आर्थिक रूप से कमज़ोरों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने के क़ानून उच्च शिक्षा और रोज़गार में समान अवसर देकर सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है.

नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी

"आरक्षण केवल आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी वंचित वर्ग के हित के लिए एक सकारात्मक उपाय है. इसलिए केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है.

एससी/एसटी और ओबीसी को ईडब्लूएस कोटे से बाहर रखना भी संवैधानिक तौर पर सही है. पचास फ़ीसदी तय आरक्षण सीमा के अतिरिक्त ईडब्लूएस आरक्षण संवैधानिक है."

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी

नौकरियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने यह फ़ैसला बहुमत के आधार पर सुनाया. चीफ़ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली पाँच जजों की बेंच ने बहुमत से ईडब्लूएस कोटे के पक्ष में फ़ैसला सुनाया और कहा कि 103वां संविधान संशोधन वैध है.

104वां संविधान संशोधन

104वां संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण कीअवधि को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था. इससे पहले इस आरक्षण की सीमा 25 जनवरी 2020 थी. इसके अलावा अधिनियम के ज़रिये लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया.

105वां संविधान संशोधन

तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त, 2021 को '105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021' को अपनी स्वीकृति दी. संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं. यह सूची केंद्र सरकार तैयार करेगी. इसके अलावा, यह क़ानून राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों कीअपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की अपनी सूची की पहचान करने और उसे नोटिफ़ाई करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को दोबारा बहाल करना है. केंद्र सरकार के अनुसार राज्यों की शक्ति को बहाल करने का सीधा लाभ उन 671 जातियों को मिलेगा जिनकी राज्य सूचियों में की गई अधिसूचना के रद्द होने का ख़तरा था. ग़ौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद- 338 बी के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों कोसामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से सलाह लेनी अनिवार्य है. संशोधन द्वारा राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दी गई है.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्गअधिनियम, 1993 के तहत की गई थी. 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया था और राष्ट्रपति को अधिकार दिया था वह सभी उद्देश्यों के लिए किसी भी राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं.

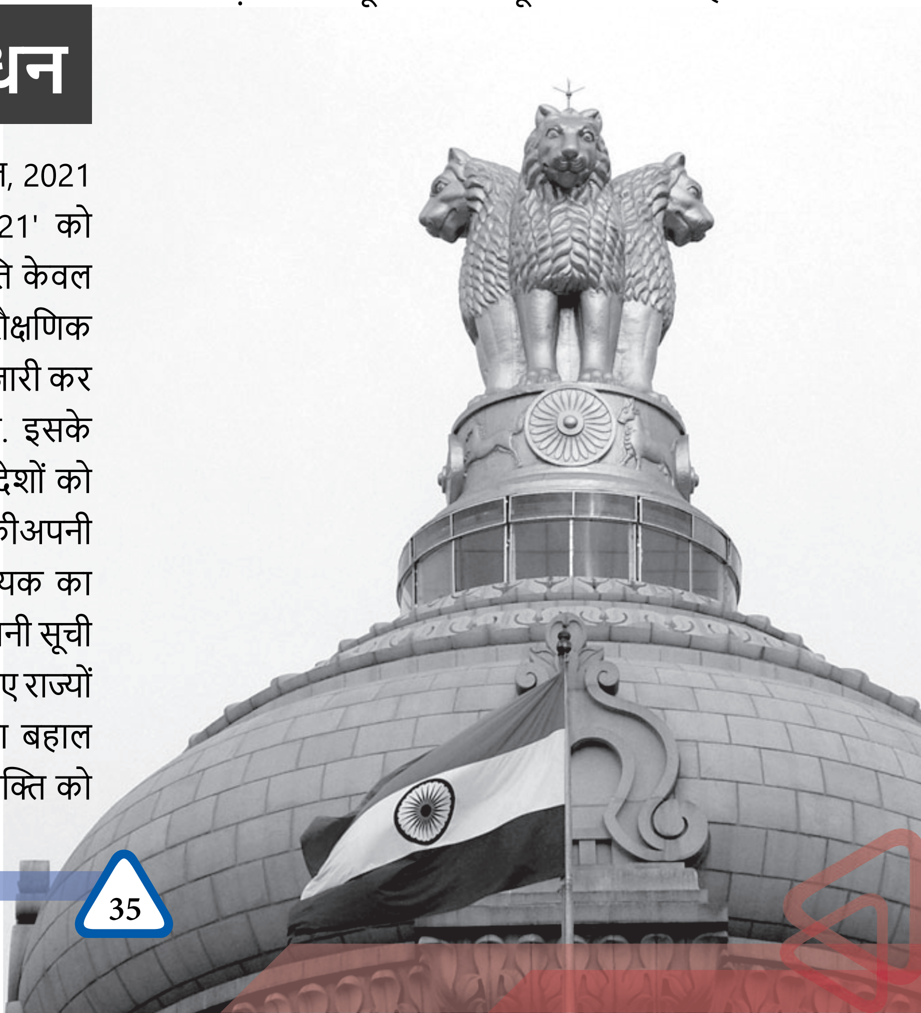

– रोहित सिंह

अमरीका की आर्थिक मंदी भारत के लिए खतरे का संकेत ?

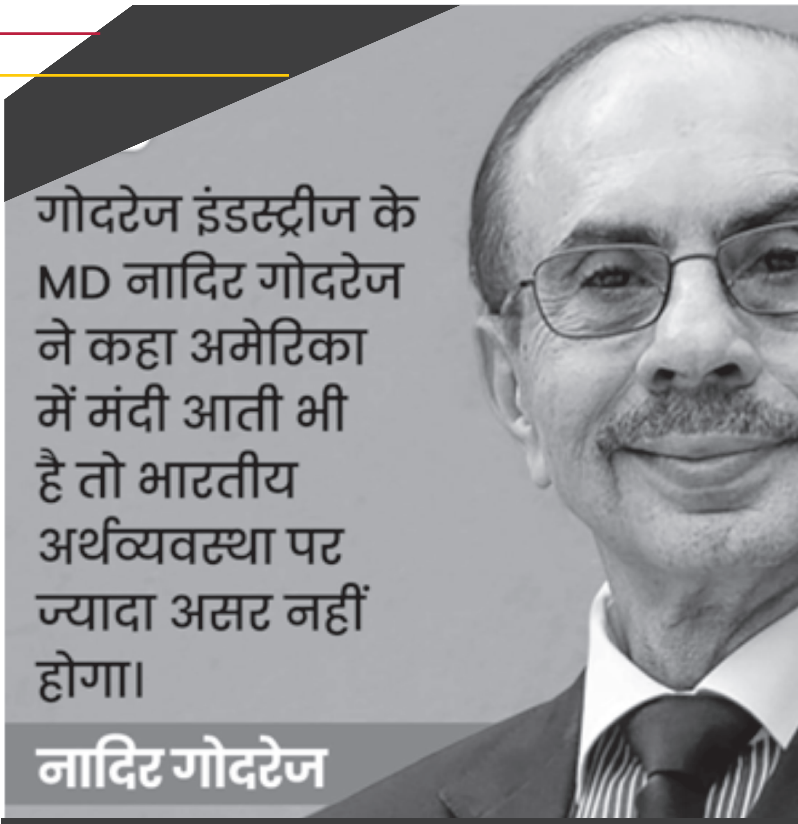

दुनियाभर में इस समय नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। ट्विटर, गूगल, मेटा सहित अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों ने सबसे ज्यासदा कर्मचारियों की छंटनी की है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, शाओमी जैसी बड़ी कंपनियों ने भी कमाई घटने की वजह से हजारों लोगों को जॉब से निकाल दिया है। यह संकट रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लो बल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ने और सप्लालई चेन में दिक्ककत आने की वजह से बढ़ा है। इसकी एक वजह कोरोना भी है। कोरोना के समय सारा व्यापार ऑनलाइन के माध्यम से होने लगा था जिसकी वजह से कर्मचारियों की भर्ती बड़े स्तर पर की गयी थी। लेकिन समय के साथ ऑफ लाइन का मार्केट भी खुल चूका है। इस बीच भारतीय आईटी कंपनियों ने भी अपनी हायरिंग पर ब्रेक लगा दिया है।

क्रंच बेस न्यूयज टैली के अनुसार, अक्टूबर तक के आंकड़े देखें तो साल 2022 में अब तक अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों ने 50 हजार से ज्याअदा कर्मचारियों की छंटनी की है। अभी कुछ और कंपनियों ने छंटनी करने की घोषणा भी कर दी है तो ज्यादातर ने हायरिंग पर विराम लगा दिया है। इसमें ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्होंने कोरोनाकाल में ऑनलाइन बिजनेस बढ़ने से बंपर कमाई की थी। इनमें छोटी और बड़ी सभी टेक कंपनियां हैं और इनके सीईओ का कहना है कि उन्होंने ज्यांदा हायरिंग कर ली थी और अब कंपनी की कमाई को देखते हुए इसे सही स्तओर पर लाया जा रहा है।

भारत में भी बीते दिनों कई स्टार्टअप्स और टेक कम्पनियों ने कर्मचारियों को निकाला है। दरअसल, रूस-यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही दुनिया महंगाई का सामना कर रही है। खाने-पीने से लेकर अन्य कई चीजें महंगी हो गई हैं। महंगाई से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरों में इजाफा कर रहे हैं, जिससे ग्रोथ कम होने का खतरा है। ग्रोथ प्रभावित होगी तो मंदी आ सकती है।

दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश अमेरिका भी ग्रोथ की कमी और मंदी की आशंका से जूझ रहा है। यहां महंगाई 40 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिस तरह से ग्लोबल कंपनियां छंटनी कर रही हैं, वैसा ही भारत की बड़ी फर्म्स भी कर सकती हैं? क्या आने वाले दिनों में भारत में लोगों को रोजगार खोना पड़ेगा? अमेरिका में मंदी आई तो भारत पर कितना असर होगा?

आर्थिक मंदी क्या होती है?

मंदी यानी किसी भी चीज़ का लंबे समय के लिए मंद या सुस्त पड़ जाना और जब इसी को अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहा जाए, तो उसे आर्थिक मंदी कहते हैं। लंबे समय तक जब देश की अर्थव्यवस्था धीमी और सुस्त पड़ जाती है, तब उस स्थिति को आर्थिक मंदी के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ घटती है, तो उसे तकनीकी रूप में मंदी का नाम देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था जब बढ़ने की बजाय गिरने लगे, और ये लगातार कई तिमाहियों तक होती रहे, तब देश में आर्थिक मंदी की स्थिति बनने लगती है। इस स्थिति में महंगाई और बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ती है, लोगों की आमदनी कम होने लगती है।

क्या मंदी का दौर आ चुका है ?

महंगाई और कंपनियों से छंटनी की प्रक्रिया पर अमेजन के फाउंडरजेफबेजोस ने एक इंटरव्यू में कहा, 'मौजूदा समय अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब है। आर्थिक गतिविधियों में रुकावट शुरू हो चुकी है। आप कई सेक्टर में छंटनी की प्रक्रिया तेज होते हुए देख सकते हैं। ऐसे में अगर अभी मंदी का दौर नहीं है, तो जल्द ही हम उस दौर में पहुंच जाएंगे।'

इसी तरह कई अन्य आर्थिक मामलों के जानकार और कंपनियों के मालिक मंदी की आशंका जता चुके हैं। ब्रोकरेजफर्मनोमुरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले सालभर के अंदर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को मंदी का सबसे बुरा दौर देखने को मिल सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर टेक कंपनियों पर ही पड़ेगा। 5-6 महीने टेक कंपनियों के लिए काफी बुरे साबित होंगे। जुलाई में विश्व बैंक का भी एक बयान आया था। कहा गया था कि इस साल के अंत तक दुनिया की आर्थिक प्रगति कम होने की आशंका है। इसलिए ज्यादातर देशों को आर्थिक मंदी की तैयारी कर लेनी चाहिए। पूरी दुनिया ज्यादा महंगाई और कम विकास दर से जूझ रही है, जिसकी वजह से 1970 के दशक जैसी मंदी आ सकती है। दुनियाभर में इसका असर दिखने भी लगा है।

अमेरिकी मंदी का भारत पर कितना असर होगा ?

पिछली मंदी जैसे कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस और 2000 के दशक की शुरुआत में डॉटकॉमक्रैश के कारण आई थी। 2008 की मंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, लेकिन भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा था। अभी महंगाई बड़ी समस्या बनी हुई है जो पर्चेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति और बचत को कम कर देती है। महंगाई से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है जिससे ग्रोथ प्रभावित हो सकती है।

अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्य वस्थाय है, लिहाजा यहां मंदी आने का असर कम या ज्यादा सभी इकोनॉमीज पर होगा। भारत पर इसके असर की बात करें तो भारत कई उत्पाबदों के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। इसके अलावा यहां की कई आईटी कंपनियों का बिजनेस अमेरिका पर निर्भर है। हालांकि भारत के बड़े कंज्यूमर मार्केट के साथ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन फैसिलिटी अमेरिकी मंदी का ज्यादा असर नहीं होने देगी। बीते दिनों गोदरेज इंडस्ट्रीज के MD नादिर गोदरेज ने कहा था, 'मुझे

नहीं लगता है कि अमेरिका में लंबे समय तक की मंदी का कोई बड़ा खतरा है। मेटल और खाने की चीजों के दाम कम हो गए हैं।कच्चे तेल में भी गिरावट शुरू हो गई है। ऐसे में महंगाई घटेगी और मंदी की आशंका कमजोर होगी। वैसे अमेरिका में मंदी आती भी है तो भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यात पर ज्यादा असर नहीं होगा।'

भारत पर मंदी का खतरा कितना बड़ा है?

भारत में महंगाई अप्रैल में 7.79% पर पहुंच गई थी। RBI की ब्याज दरों में तीनबार में 1.40% के इजाफे के बाद जुलाई में रिटेल महंगाई घटकर 6.7% पर आ गई है। कमोडिटी के दाम भी अब नीचे आने लगे हैं, लिहाजा RBI को ब्याज दरें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर भी नीतिगत दरों में अब तक की तेज बढ़ोतरी और आगे हल्के इजाफे के कारण आर्थिक विकास में मामूली गिरावट आ सकती है।

बीते दिनों ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन-कौन से एशियाई देश आर्थिकमंदी की चपेट में आ सकते हैं और किन देशों पर आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट में अर्थ शास्त्रियों ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान के आर्थिक मंदी में फंसने की संभावना 20% है। मलेशिया की 13%, वियतनाम 10%, थाइलैंड 10%, फिलीपींस 8%, इंडोनेशिया 3% और भारत की शून्य है।

क्या भारत की बड़ी फर्म्स भी छंटनी कर सकती हैं ?

रूस-यूक्रेनजंग से कमोडिटी की ऊंची कीमतों से कुछ

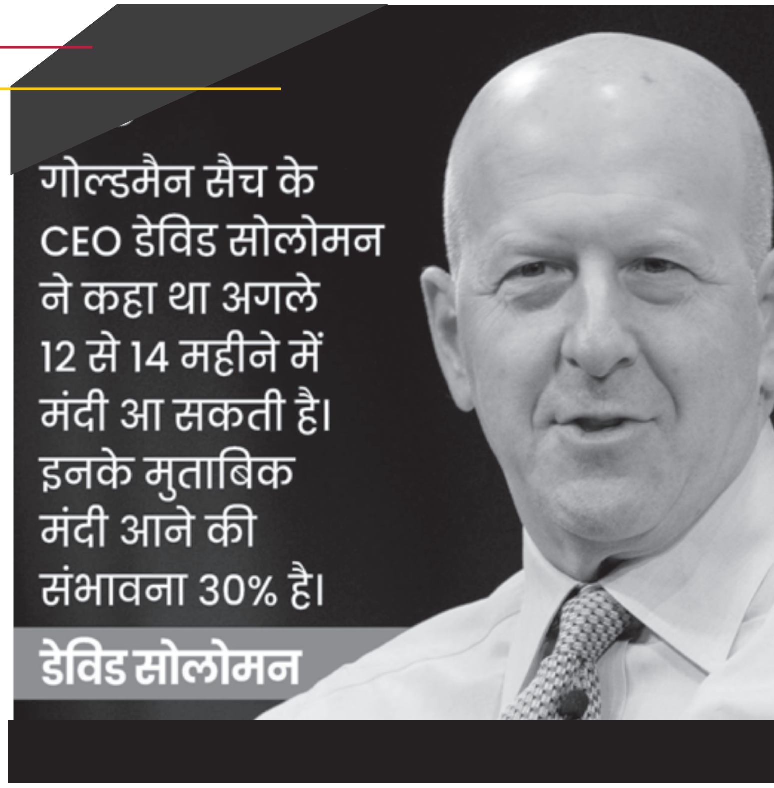

इंडस्ट्री काफी प्रभावित हुई हैं, लेकिन कुछ को फायदा भी हुआ है। केमिकल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा हुआहै। FMCG बिजनेस थोड़ा प्रभावित हुआ है। रियलएस्टेट पर ज्यादा असर नहीं हुआ है। फूड बिजनेस महंगाई से प्रभावित हुए हैं। हालांकि अब कमोडिटी कीमतों के कम होने से स्थिति में सुधार हो रहा है। ऐसे में बड़ी फर्म्स में छंटनी की आशंका कम है।

भारत पर फिलहाल असर नहीं

अमेरिकामें मंदी के डर का असर भारत पर नहीं दिख रहा। भारत में जॉब ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत में मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर टॉप10 प्राइवेट कंपनियों में से 8 ने 3 लाख सेज्यादा लोगों को जॉब पर रखा। 2020-21 में ये संख्या केवल एक लाख के करीब थी। रिटेल, IT सर्विसेज और बैंकिंग एजुकेशन, टेलीकॉम, E - कॉमर्स, हेल्थकेयर, FMCG और एयरलाइंस में भी भर्ती में तेजी आई है।

किस कंपनी में कितनी छंटनी

एपल, माइक्रोसॉफ्ट में छंटनी

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टेक दिग्गज एपल ने बीते दिनों 100 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इम्प्लॉइज को निकाल दिया। ये इम्प्लॉइज HR डिपार्टमेंटमें थे और नए इम्प्लॉइज की भर्ती का काम इनके पास था। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार एपल ने खर्च को कंट्रोल करने के लिए ये फैसला लिया है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि छंटनी की एक वजह एपल की मौजूदा बिजनेस जरूरतों में बदलाव भी है। इसके अलावा दूसरी कंपनियों की तरह एपल को भी मंदी का डर सता रहा है। बीते दिनों एपल ने अपनी अर्निंग्स कॉल में कहा था कि वह अपने खर्च को लेकर सतर्क है। इस बयान से ऐसा लगता है कि कंपनी कुछ कर्मचारियों को निकालकर पैसे बचाने की कोशिश कर रही है।

अभी हाल ही में गूगल ने कहा था कि वह हायरिंग प्रोसेसस्लो करने जा रही है।गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा था- कंपनी के पास बहुत कर्मचारी हैं, लेकिन काम काफी कम है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी 2 हजार से ज्यादा कर्मचारियों कीछंटनी की है। नेटफ्लिक्स, शॉपिफाई, कॉइनबेस और अलीबाबा जैसी कंपनियों ने भी कुछ हद तक कॉस्ट कटिंग के चलते कर्मचारियों को निकाला है।

गूगल का मुनाफा घटा

गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के मुनाफे में लगातार दूसरी तिमाही (Q2 2022) में गिरावट आई थी। अल्फाबेट ने 2022 की दूसरी तिमाही के दौरान लगभग 16 अरब डॉलर का प्रॉफिट कमाया, जो पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 18.5 अरब डॉलरथा।

कंपनी के मुनाफे में कमी का कारण उसका ज्यादा खर्च करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि Q2 2021 की तुलना में Q2 2022 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट घटा है। इस तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 69.7 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के तीसरे क्वॉर्टर में 61.9 अरब डॉलर था।

2021 की तुलना में गूगल रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों परलगभग 3 अरब डॉलर ज्यादा खर्च कर रहा है। हेडकाउंट की बात करें तो Q2 2021 में गूगल में 144,056 इम्पलॉई थे। Q2 2022 में यह संख्या बढ़कर 174,014 हो गई।

फेसबुक के रेवेन्यू में पहली बार गिरावट

फेसबुकको पेरेंट कंपनी मेटा को पिछले तीन महीनों में दोहरी मार झेलनी पड़ी है।टिकटॉक से बढ़ते कॉम्पिटिशन और एडवर्टाइजर्स की घबराहट के बीच पहली बार उसके रेवेन्यू में गिरावट आई और लगातार तीसरी तिमाही में प्रॉफिट घट गया। कंपनी के CEO मार्क जुकर बर्ग ने कहा, 'ऐसा लगता है कि हम आर्थिक मंदी में प्रवेश कर चुके हैं जिसका डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पर प्रभाव पड़ेगा। मैं कहूंगा कि स्थिति एक क्वार्टर पहले की तुलना में बदतर लगती है।'

अमेरिकी कंपनियों ने एक्सपैन्शन रोका

महंगाई, धीमी होती अर्थव्यवस्था, अमेरिका और यूरोप में मंदी के डर और यूक्रेन-रूसयुद्ध की चिंताओं के बीच कंपनियां अपना एक्सपैन्शन रोक रही हैं। मेटा, ट्विटर और टेस्ला सहित अन्य कुछ कंपनियों ने भी अमेरिकी बाजार मेंअनिश्चितता के बीच हायरिंग को स्लो कर दिया है।

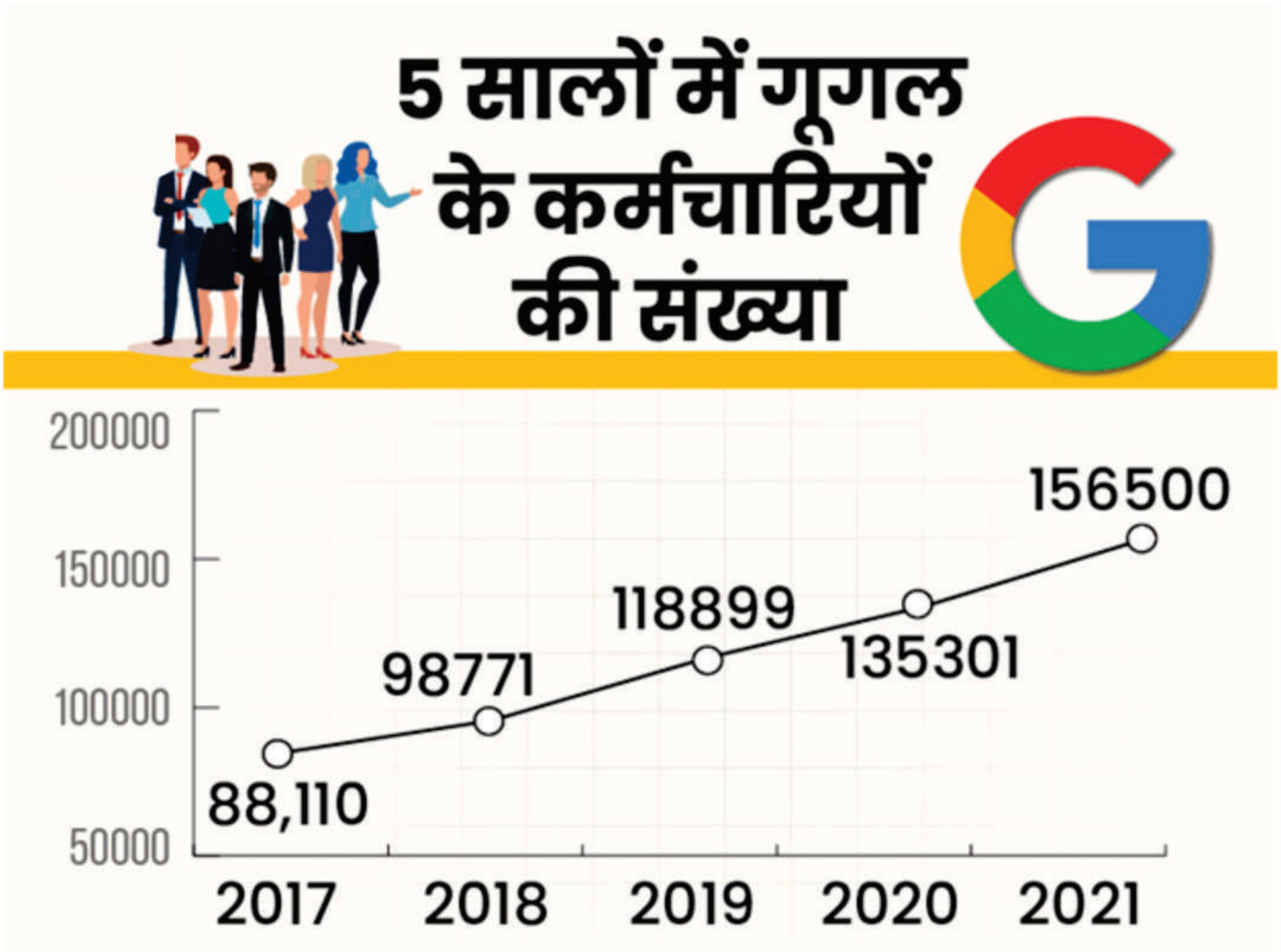

स्टाफिंग स्पेशलिस्ट एक्सफेनो की अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक, एपल, अमेजन, नेटफ्लिक्स, माइक्रो सॉफ्ट और गूगल में कुल एक्टिव ओपनिंग 9,000 से कम थी। इन छह कंपनियों में आमतौर पर 40 हजार से अधिक एक्टिव जॉब ओपनिंग्स रहती है। इन कंपनियों ने ग्लोबल ट्रेंड को देखते हुए भारत में भी हायरिंग को रोक दिया है।

अन्य इंडस्ट्री पर असर नहीं

अमेरिका में टेक सेक्टर में हायरिंग में कटौती का अभी तक अन्य इंडस्ट्री में हायरिंग पर असर नहीं पड़ा है, जो रेड-हॉट बने हुए हैं। जुलाई में अमेरिकी इकोनॉमी ने 528,000 जॉब ऐड किए। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि टेक सेक्टरकी छंटनी का मतलब यह नहीं कि बड़े लेवल पर हायरिंग स्लोडाउन आ रहा है।

भारतीय स्टार्टअप्स में छंटनी

इंडियन स्टार्टअप्स साल के पहले 6 महीने में करीब 12,000 इम्पलॉइज को निकाल चुके हैं। साल खत्म होते-होते यह संख्या 60 हजार के पार पहुंच सकती हैं। ओला, ब्लिंकिट, बायजूस, अनएकेडमी, वेदांतू, कार्स 24,

जनवरी से 30 जून तक की छंटनी का आंकड़ा

स्टार्टअप	सेक्टर	छंटनी	कारण
ओला कैब	सर्विस	2,100	पुनर्गठन
ब्लिंकिट	ईकॉमर्स	1,600	लागत कटौती
व्हाइटहैट जूनियर	एजुटेक	1,300	लागत कटौती
लीडो लर्निंग	एजुटेक	1,200	वित्तीय संकट
अनएकेडमी	एजुटेक	925	लागत कटौती
वेदांतु	एजुटेक	624	लागत कटौती
कार्स24	ईकॉमर्स	600	लागत कटौती
एमफाइन	हेल्थटेक	600	वित्तीय संकट
ट्रेल	ईकॉमर्स	400	लागत कटौती
टॉपर	एजुटेक	300	लागत कटौती

सोर्स- मीडिया रिपोर्ट, कंपनी की घोषणाएं

मोबाइल प्रीमियरलीग, लीडोलर्निंग, एमफाइन, ट्रेल, फरलैंको और कई दूसरी कंपनियां इस साल अब तक हजारोंकर्मचारियों की छंटनी कर चुकी हैं।

मार्केटिंग खर्च 30-40% कम किया

शेयरचैटऔर मोजो के चीफ कॉमर्शियलऑफिसर अजीत वर्गीज ने कहा-स्टार्ट-अप निश्चितरूप से ज्यादा कॉस्टकॉन्शियस हो गए हैं। चाहे वह क्लाउड हो, यूजर एक्विजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, या लोग - सभी पर कम खर्च किया जा रहा है। हमने स्टार्ट-अप्स को मार्केटिंग कॉस्ट में 30-40% या इससे भी अधिक की कटौती करते देखा है। वर्गीज ने कहा कि अधिक स्थापित और लाभप्रद लिस्टेड कंपनियों की मार्केटिंग स्पेंड्स में 10-15% की कमी आई है। फिनटेक, एडटेक और क्रिप्टो करेंसी जैसे सेक्टर्स में सबसे अधिक गिरावट देखी गई।

मंदी और जॉब का कनेक्शन

मंदीकी शुरुआत में, जैसे-जैसे कंपनियां कम मांग, घटते मुनाफे और ऊंचे कर्ज का सामना करती हैं, कई कंपनिया कॉस्टकटिंग करने के लिए इम्पलॉइज की छंटनीशुरू कर

देती हैं। बढ़ती बेरोजगारी कई संकेतकों में से एक है जो मंदी कोपरिभाषित करती है। मंदी में कंज्यूमर कम खर्च करते हैं और इंडस्ट्रियलप्रोडक्शन भी धीमा हो जाता है।

अमेरिका पर मंदी का कितना खतरा ?

अमेरिका में 2022 के जून क्वार्टर के दौरान ग्रोथ 0.9% एनुअलाइज्डरेट से धीमी होगई। ये लगातार दूसरा क्वार्टर था जब अमेरिकी इकोनॉमी सिकुड़ी थी। फाइनेंशियल टाइम्स और इनिशिएटिव ऑन ग्लोबल मार्केट्स के किए गए 49 अमेरिकी मैक्रोइकोनॉमिस्ट्स के एक सर्वे में 2023 तक मंदी के आने की आशंका जताई गई है। सर्वे में दो-तिहाई से अधिक इकोनॉमिस्ट का मानना था कि 2023 में मंदी आएगी।

सी-गेट:

हार्डड्राइव बनाने वाली कंपनी सी-गेट टेक्नोलॉजी ने पिछले महीने बताया था कि 8 फीसदी कर्मचारियों की छंटने करने की तैयारी है, जिसमें करीब 3,000 कर्मचारी होंगे.

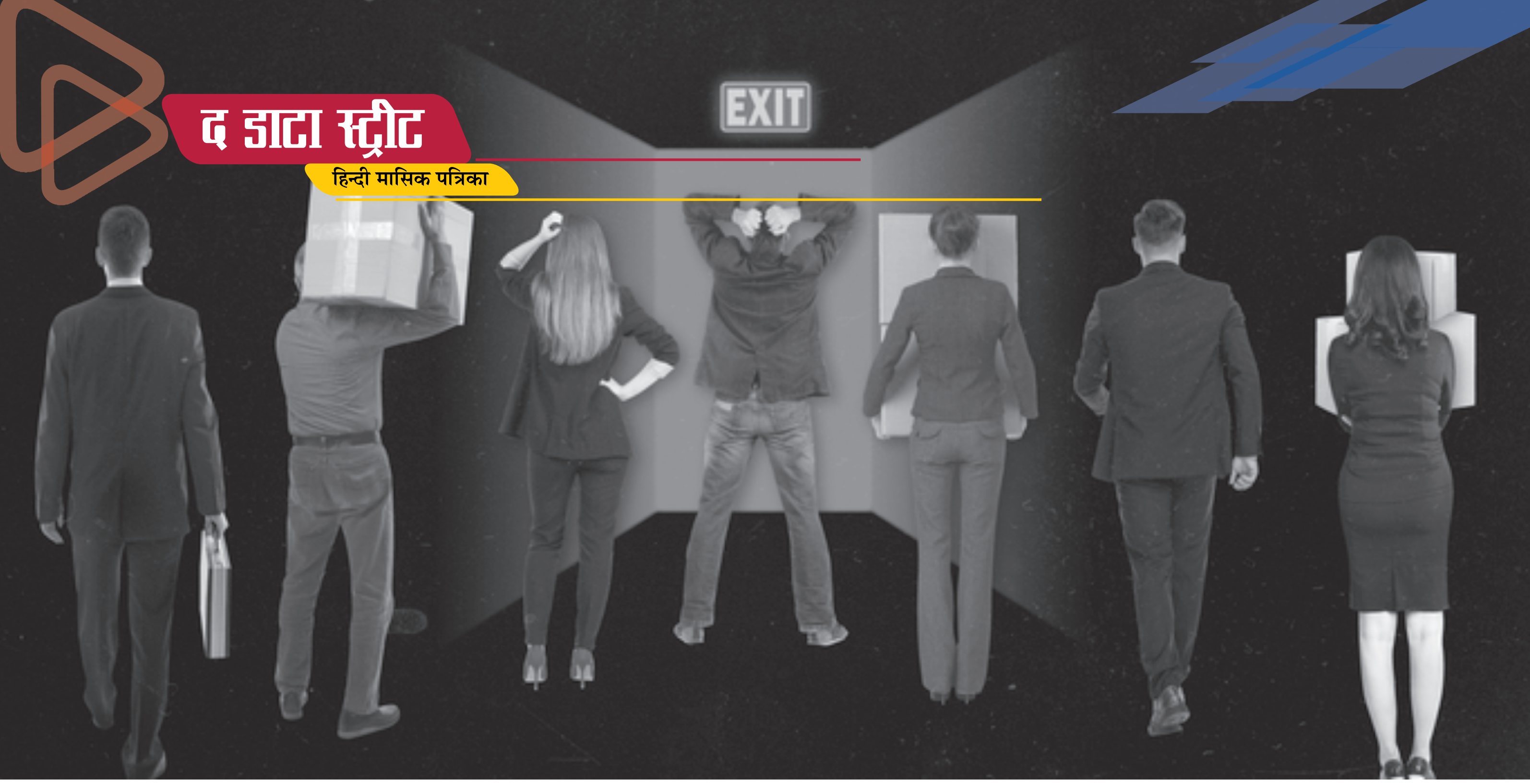

इंटेल:

कंपनी की तैयारी अगले साल तक करीब 18 हजार करोड़ रुपये बचत करने की है और इसके लिए बड़ी संख्या में छंटनी की तैयारी कर रही है. इससे 20 फीसदी कर्मचारियों पर असर पड़ेगा.

माइक्रोसॉफ्ट:

कंपनी ने अपनी कमाई घटने की वजह से खर्चों में कटौती की घोषणा की है. इसके तहत जुलाई में ही कंपनी करीब 1 फीसदी कर्मचारियों की छंटीनी कर चुकी है.

ट्विटर:

एलन मस्कन के हाथ में कमान आते ही कंपनी ने करीब 50 फीसदी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है. मस्कर ने कहा था कि कंपनी को अभी 40 लाख डॉलर का रोजाना घाटा हो रहा और इससे निपटने के लिए छंटनी जरूरी है.

क्वॉइनबेस:

अमेरिका स्थित इस कंपनी ने अपने 18 फीसदी स्टाटफ को निकाल दिया है, जिसमें करीब 1,100 कर्मचारी आते हैं. कंपनी का कहना है कि मंदी की आशंका को देखते हुए कॉस्ट कटिंग करना जरूरी हो गया था.

नेटफ्लिक्सत :

इस ओटीटीप्ले टफॉर्म को भी तगड़ा घाटाहुआ है और कंपनी ने अभी तक 500 कर्मचारियों को निकाला है. कंपनी का कहना हैकि साल 2022 उसके लिए काफी टफ रहा है.

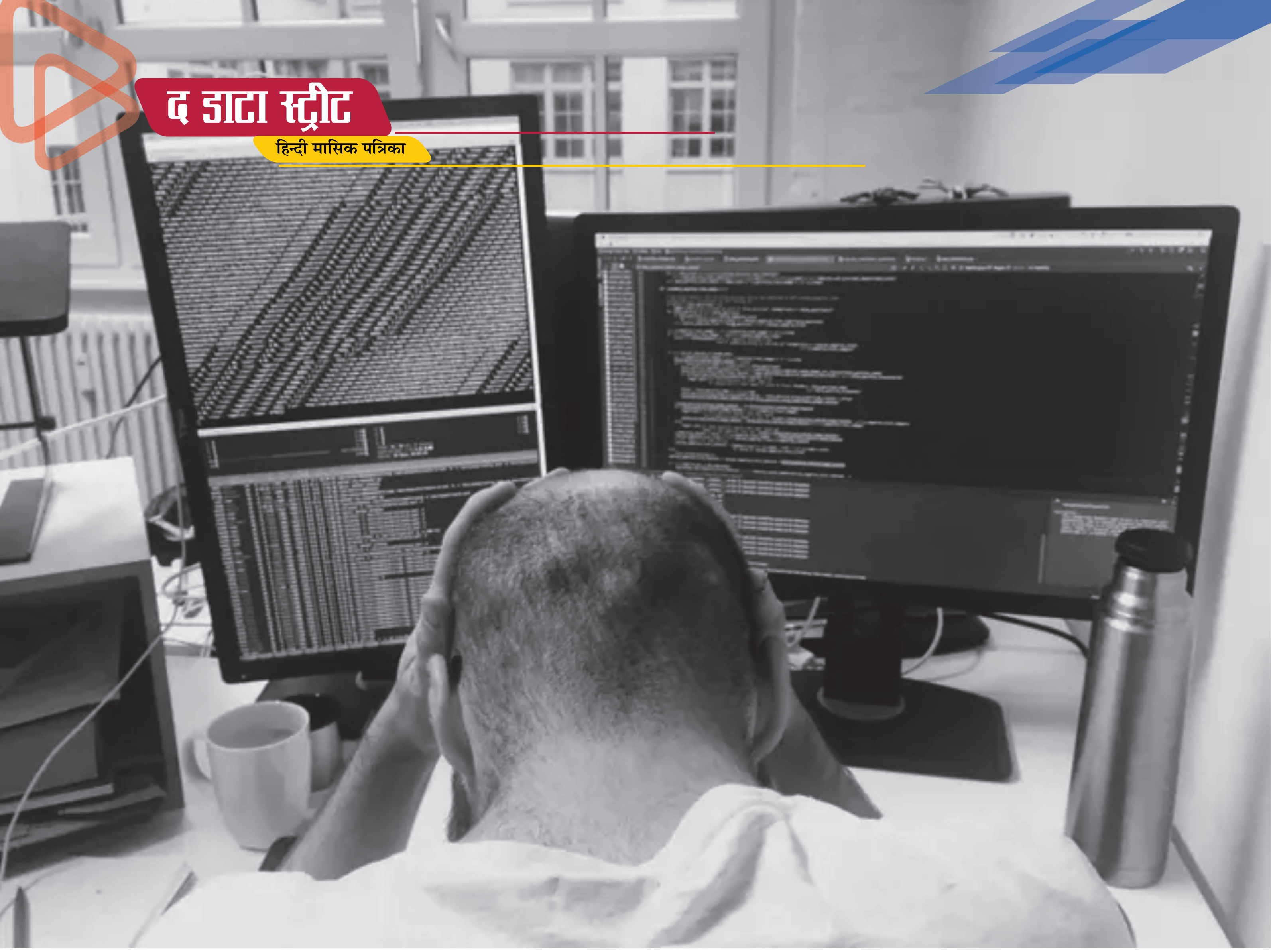

स्नैलप :

कंपनी के स्टॉक में करीब 40 फीसदी की गिरावटआई है और अब 20 फीसदी छंटनी की तैयारी है. इस कदम से करीब 1,000 कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा है.

शॉपिफाई :

इस ई-कॉमर्स कंपनी ने भी 10 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है, जिससे 1,000 से ज्याफदा कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है.

लिफ्ट :

कैलिफोर्निया की यह कंपनी पिछले महीने ही अपने वर्क फोर्स को करीब 13 फीसदी घटा चुकी है और 700 कर्मचारियों को निकाला गया. कंपनी ने सितंबर से हायरिंग भी बंद कर दी है.

स्ट्राईइप :

इस फिनटेक कंपनी के पास करीब 8 हजार कर्मचारी हैं और यह करीब 14 फीसदी वर्क फोर्स घटाने की तैयारी में है. इससे कंपनी के 1,120 कर्मचारियों को हाथ धोना पड़ेगा.

ओपनडोर :

रियलएस्टेकट की स्टा र्टअप कंपनी ओपनडोर का कहना है कि 18 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी है, जिससे 550 लोग निकाले जाएंगे.

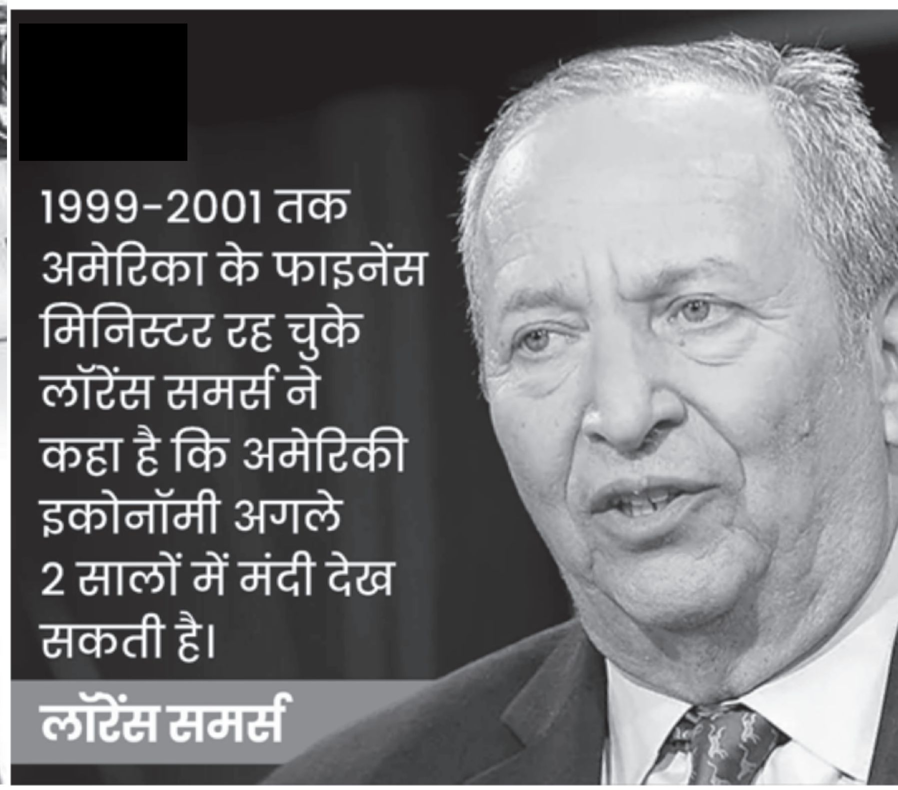

शाओमी:

चीन की स्मार्ट फोन मैन्युफैक्चरर शाओमी (Xiaomi) ने 900 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने आर्थिक मंदी के बीच करीब 3% कर्मचारियों को निकाल दियाहै।

भारतीय कंपनियों ने बंद कर दी हायरिंग

छंटनी और नौकरियों पर लगाम सिर्फ अमेरिकी कंपनियां ही नहीं लगा रहीं, बल्कि भारतीय आईटी कंपनियों ने भी हायरिंग पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है. देश की 10 बड़ी आईटी कंपनियों में से 5 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. आईटी कंपनियों की कुल लागत में 55 से 65 फीसदी हिस्सेदारी कर्मचारियों पर आने वाले खर्च की होती है. यही कारण है कि कंपनियों ने हायरिंग प्रक्रिया सुस्त कर दी है. विप्रो के कर्मचारियों की संख्या 6.5 फीसदी घटी है. एलएंडटी ने 5 फीसदी और टेक महिंद्रा ने 1.4 फीसदी हेडकाउंट घटा दिया है.

M/s. Chayhan Pen Center

Deals in: All kind of Stationery & Govt. General order Supplier

JITENDER KUMAR SINGH : 9335244977

53- Gwynne Road, Aminabad, Lucknow 226018

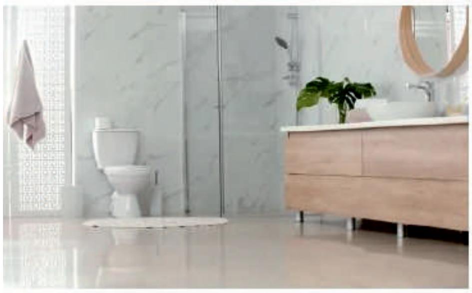

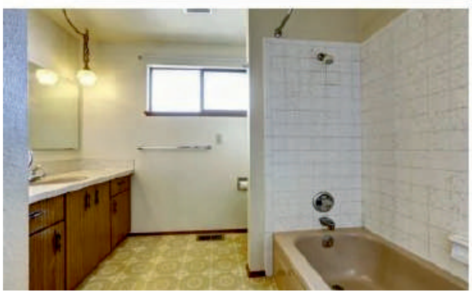

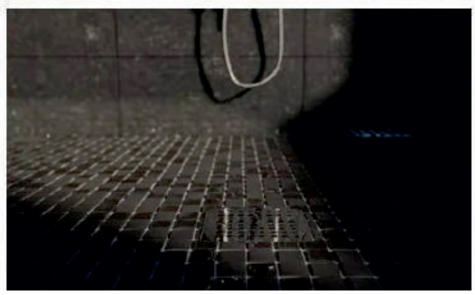

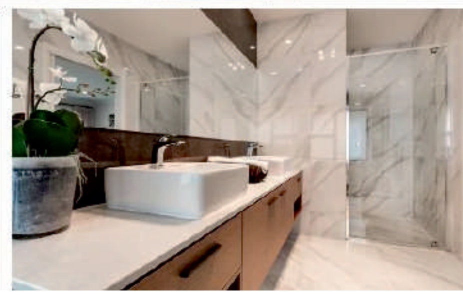

VMT

Vaishno Marble & Traders

Deals in: All types of Marble, Granite Kota, Tiles etc.

Mobile: 9415034158, 9369106489